जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 52 संख्याः 03 प्रभात कोटा, गुरूवार 15 अक्टूबर, 2026 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'अमेरिका में मोदी विरोधी लोग दीपके और सीजेपी को "फण्ड" कर रहे हैं'

अमेरिकन सिंगर मेरी मिलीबेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया, हालांकि, उन्होंने फंड करने वालों के नाम नहीं बताए

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। अमेरिका में रहने वाले कुछ दानदाताओं द्वारा अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को पैसा देने के आरोप ने भारत में असहमति, विदेशी दखल और राजनीतिक आंदोलनों की फंडिंग को लेकर चल रही बहस में एक संवेदनशील मुद्दा खड़ा कर दिया है। अगर यह दावा सही साबित होता है, तो देश के भीतर राजनीतिक गतिविधियों में बाहरी लोगों की भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं। तथापि, खतरा यह है कि दस्तावेजी सबूतों के बिना यह गंभीर आरोप सिर्फ एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव बनकर रह जाएगा, जिसे साबित करने वाले तथ्य मौजूद नहीं हैं।

अमेरिकी गायिका और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की समर्थक मैरी मिलबेन ने सोशल मीडिया पर यह आरोप लगाया कि मोदी का विरोध करने वाले अमेरिका के कुछ दानदाता दीपके और सीजेपी को पैसा दे रहे हैं, ताकि भारत में शासन व्यवस्था को बाधित किया जा सके। हालांकि, इस विवाद पर अब तक सामने आई सार्वजनिक रिपोर्टों में कथित दानदाताओं की पहचान, दी गई रकम या ऐसे किसी भरोसेमंद वित्तीय लेन-देन का पता नहीं चला है, जो उन्हें इस आंदोलन से जोड़ता हो।

राजनीतिक रूप से यह अंतर मायने रखता है। अगर किसी घरेलू संगठन को विदेश से फंडिंग मिलने की बात साबित होती है, तो उसके पैसों के स्रोत, कानूनी स्थिति और लागू नियमों के पालन की जांच हो सकती है। लेकिन किसी विदेशी सरकार की भागीदारी या बाहर से चलाए जा रहे राजनीतिक अभियान का आरोप साबित करने के लिए अतिरिक्त सबूत जरूरी हैं। केवल निजी विदेशी चंदे से ये बातें अपने आप साबित नहीं हो जातीं।

दीपके ने आंदोलन की फंडिंग के बारे में अलग बात कही है। 10 अक्टूबर को प्रकाशित लोकसत्ता के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे और उनके दोस्त, जिनमें आशुतोष रांका भी शामिल हैं, पैसे का योगदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद, क्राउडफंडिंग, यानी आम लोगों से छोटे-छोटे योगदान लेकर पैसा जुटाने की योजना है। उन्होंने कहा, शुरुआती विरोध प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने व्यावहारिक मदद दी थी।

इन बातों से आंदोलन के लिए पैसों के कम से कम कुछ स्रोतों की जानकारी मिलती है। लेकिन इससे उसके पूरे वित्तीय हिसाब का पता नहीं चलता और न ही यह पूरी तरह साबित होता है कि उसे किसी अन्य स्रोत से पैसा नहीं मिला।

14 अक्टूबर को दीपके ने मिलबेन के दखल पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीयों को अपने देश के राजनीतिक मतभेदों को बिना बाहरी दखल के सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। उनके जवाब ने इस बात की ओर ध्यान खींचा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अमेरिकन सिंगर के इस दावे के बाद भारत में विदेशी फंडिंग के मुद्दे पर भारी बहस छिड़ गई। हालांकि, दीपके ने पूर्व में कहा था कि वे और आशुतोष रांका आर्थिक योगदान देते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सीजेपी के रजिस्ट्रेशन की कोशिश चल रही है और फिर वे क्राउड फंडिंग से धन जुटाएंगे।
- हालांकि, अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित होता हो कि सीजेपी को विदेशी फंडिंग मिल रही है, फिलहाल यह मुद्दा आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित लग रहा है।

अदालती आदेश के बाद भी नीट आयुष काउंसलिंग में शामिल नहीं किया

जयपुर, 14 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने, अदालती आदेश के बावजूद, याचिकाकर्ता को नीट आयुष काउंसलिंग-2026 में शामिल नहीं करने पर नीट आयुष काउंसलिंग चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। इसके साथ ही, अदालत ने चेयरमैन को 16 नवंबर को शपथ पत्र पेश कर यह भी बताने के लिए कहा है कि उन्होंने हाईकोर्ट के 24 सितंबर के आदेश की पालना में याचिकाकर्ता की काउंसलिंग और दस्तावेजों का सत्यापन किया या नहीं। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने ये आदेश प्रणवेन्द्र गुर्जर की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता ने बीएएमएस में प्रवेश के लिए नीट आयुष काउंसलिंग 2026 में रजिस्ट्रेशन करवाया था। नीट आयुष काउंसलिंग में प्रवेश के लिए एक वर्ग एनआरआई के बराबर फीस जमा कराने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए था। इसमें एनआरआई अभ्यर्थी के नहीं आने पर आयुष के लिए प्रवेश दिया जाना था। हर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हाई कोर्ट ने नीट आयुष काउंसलिंग चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी किया।

'ब्रिक्स समिट से दूर रह कर बड़ा मौका गंवा दिया बाँग्लादेश ने'

बाँग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्तमान प्रधानमंत्री की राजनैतिक परिपक्वता पर सवाल उठाए

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। पिछले महीने भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस कदम को अपरिपक्व बताते हुए कहा है कि इससे उनके देश के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा है।

इस साल की शुरुआत में सत्ता संभालने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेतृत्व वाली सरकार के प्रमुख रहमान ने भारत की ओर से निमंत्रण दिए जाने के बावजूद 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ढाका का कहना था कि निमंत्रण रहमान को बिम्सटेक के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में दिया गया था, न कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर। बांग्लादेश चाहता था कि रहमान की पहली भारत यात्रा बहुपक्षीय सम्मेलन के बजाय द्विपक्षीय हो। भारत ने इसके जवाब में कहा कि रहमान को द्विपक्षीय बातचीत और ब्रिक्स के आउटरीच सत्र, दोनों के लिए अलग-अलग निमंत्रण दिए गए थे। अंततः बांग्लादेश ने सम्मेलन में अपना कोई आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं भेजा।

एक समाचार एजेंसी को हाल ही में दिए साक्षात्कार में हसीना ने कहा कि बांग्लादेश ने आर्थिक और सामाजिक विकास के कई महत्वपूर्ण अवसर गंवा दिए। उन्होंने कहा, ब्रिक्स केवल एक कूटनीतिक बैठक नहीं है। इसमें प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आती हैं और व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी तथा विकास के क्षेत्रों में सहयोग के अवसर पैदा होते हैं। इसमें भाग लेकर बांग्लादेश मूल्यवान अनुभव हासिल कर सकता था और नए अवसरों के द्वार खोल सकता था... वह अवसर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हालांकि, बाँग्लादेश की ओर से कहा गया है कि रहमान को बाँग्लादेश के प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं बुलाया गया था, इसके अलावा वे पहली भारत यात्रा बहुपक्षीय समिट के बजाय द्विपक्षीय वार्ता के लिए करना चाहते थे।
- लेकिन चर्चा है कि असल में नई दिल्ली में शेख हसीना की मौजूदगी की वजह से वे समिट में शामिल नहीं हुए।
- शेख हसीना ने रहमान के इस फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि इससे बाँग्लादेश को नुकसान होगा। इसी के साथ उन्होंने दिसम्बर में स्वदेश वापसी की घोषणा की।

एयर फ्रांस ने इज़रायल की उड़ानों से पाकिस्तानी पायलटों को हटाया

इज़रायल ने उन देशों के विमानन कर्मचारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए है, जिनसे उसके कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं, इसलिए एयर फ्रांस ने यह फैसला लिया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। एयर फ्रांस ने पाकिस्तानी पायलटों और चालक दल के सदस्यों को इज़रायल आने-जाने वाली उड़ानों में ड्यूटी करने से रोक दिया है। यह कदम यहूदी देश इज़रायल द्वारा उन देशों के एयरलाइन क्रू के लिए प्रतिबंध सख्त करने के बाद उठाया गया है, जिनके साथ उसके राजनयिक संबंध नहीं हैं। यह फैसला 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की एक उड़ान में ओमान के सह-पायलट द्वारा कथित तौर पर आतंकवादी हमला करने की कोशिश के बाद लिया गया है। ओमान उन देशों में शामिल है, जिनके इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- एयर फ्रांस ने पाकिस्तान सहित 31 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों के नागरिकों को इज़रायल की उड़ानों में तैनात नहीं किया जाएगा।
- इसी के साथ शिकागो की यूनाइटेड एयरलाइन्स ने भी अपने पायलटों को इज़रायल द्वारा लगाए गए राष्ट्रीयता आधारित प्रतिबंधों की जानकारी अपने स्टाफ को दी।
- चैक रिपब्लिक की एयरलाइन स्मार्टविंग्स ने भी इज़रायल के प्रतिबंध लागू करने की पुष्टि की।

वाहनों पर काली फिल्म व रंगीन शीशे क्यों लगे हैं?

जयपुर, 14 अक्टूबर। ने रोक के बावजूद प्रदेश की सड़कों पर चल रहे वाहनों पर काली फिल्म और रंगीन शीशे लगे होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में मुख्य सचिव, परिवहन विभाग के सचिव, परिवहन आयुक्त व डीजीपी को पक्षकार बनाया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश एक डेथ रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर दिए। अदालत ने हाईकोर्ट प्रशासन को कहा कि वह इस मामले को सीजे के समक्ष रखे, ताकि इसे जनहित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- बार एसोसिएशन सदस्यों ने हाई कोर्ट से कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है।

हाइजैक अलर्ट के बाद एयर इंडिया विमान जयपुर डायवर्ट

जाँच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, विमान को दोपहर 2:24 बजे दिल्ली रवाना कर दिया गया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक उड़ान को बुधवार सुबह, हाईजैक अलर्ट मिलने के बाद, जयपुर डायवर्ट कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार, हवाई अड्डा अधिकारियों ने हाईजैक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए आमतौर पर अपनाई जाने वाली उच्चतम स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की।

बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान, उड़ान संख्या 2030, सुबह 9.45 बजे, अपने निर्धारित गंतव्य दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर, जयपुर में सुरक्षित उतर गया। विमान के जमीन पर उतरने के बाद अधिकारियों ने सावधानी बरतते हुए उसके पास पहुंचकर यात्रियों के उतरने के लिए सीढ़ियां लगवाईं।

अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। विमान की पूरी तरह जांच किए जाने के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतरने की अनुमति दी गई। एयरलाइन ने बुधवार को पहले बताया था कि यात्रियों को यात्रा की तारीख बदलने के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के विकल्प या टिकट रद्द करने की स्थिति में पूरा रिफंड देने की पेशकश की गई।

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को विमान से कुछ सेकंड के लिए स्क्वॉक-7500 कोड का संकेत मिला था। विमानन क्षेत्र में इस कोड का इस्तेमाल हाईजैक की स्थिति का संकेत देने के लिए किया जाता है। इसके बाद एटीसी ने जयपुर सहित, संबंधित एजेंसियों को सूचना दी। सुबह करीब 9:10 बजे विमान का मार्ग बदलकर जयपुर की ओर कर दिया गया और 9:45 बजे इसकी लैंडिंग कराई गई।

विमान उतरने के बाद, उसे पार्किंग क्षेत्र से दूर आइसोलेशन-बे में रखा गया। एयरपोर्ट पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) सहित, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला। विमान में सवार करीब 300

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- एयर इंडिया की फ्लाईट एआई2030 (बोइंग 787 ड्रीमलाइनर) को सुबह 9:45 बजे जयपुर हवाई अड्डे पर उतारा गया।
- विमान को आइसोलेशन में रखा गया। विमान में 300 यात्री सवार थे।
- सूत्रों का कहना है कि तकनीकी खराबी से अलर्ट का बटन दब गया था, इसकी वजह से हाईजैक का संदेश अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुँचा जिसके बाद विमान को जयपुर डायवर्ट किया गया।

'तिरंगे के साथ कनॉट प्लेस के सेन्ट्रल पार्क में 16 को इकट्ठे हों'

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने लोगों से 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शाम को इकट्ठा होने और साथ में तिरंगा लाने की अपील की है। उनका यह बयान सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के बाद आया है। सीजेपी का आरोप है कि दोनों को जंतर मंतर में तिरंगा लहराने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है।

दीपके आज सुबह दिल्ली पहुंचे और शाम को उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से यह अपील की। उन्होंने कहा कि उनके साथियों को तिरंगा लहराने के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सीजेपी के अभिजीत दीपके ने लोगों से अपील की।

शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल कराने का आरोप लगाया

बदले में कांग्रेस ने अमित शाह से एसआईआर पर पूछे तीन सवाल

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सव रिविजन-एसआईआर) को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग चल रही है। शाह एसआईआर का बचाव कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जनता द्वारा बार-बार नकारे जाने के बाद, विपक्षी दल घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना चाह रहा है। इसके जवाब में कांग्रेस ने उनसे तीन सवाल पूछे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, "एसआईआर का लगातार बचाव कर रहे केन्द्रीय गृह मंत्री से तीन बेहद सरल और सीधे सवाल हैं। कितने घुसपैठियों की पहचान की गई है? कितने घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं? कितने घुसपैठियों को देश से बाहर भेजा गया है?"

मंगलवार को केन्द्रीय गृह मंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूचियों के एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा था।

शाह ने पत्रकारों से कहा था, "मैं राहुल जी और उनके साथियों से कहना चाहता हूं कि वे 2029 में एक बार फिर करारी हार का सामना करने के लिए तैयार रहें। 2029 के आम चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा और कांग्रेस लगातार चौथी बार हार का सामना करेगी।"

उन्होंने कहा था, "इस देश की जनता नरेन्द्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। आप इस सच्चाई को नकार नहीं सकते।"

शाह ने कहा कि भारत की जनता "घुसपैठियों के नाम मतदाता के रूप में दर्ज कराए जाने" की राहुल गांधी की योजनाओं को जानती है।

उन्होंने कहा था, "मैं राहुल गांधी जी से सीधे पूछना चाहता हूं: क्या यह एसआईआर का नतीजा है? एसआईआर की शुरुआत तो 2024 के बाद ही हुई है।"

शाह ने कहा, "जब से आप कांग्रेस के प्रमुख नेता बने, फिर पार्टी अध्यक्ष बने और अब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तब से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। आपको आत्ममंथन करना चाहिए। मनगढ़ंत मीडिया कार्यक्रमों और झूठ को बार-बार दोहराने से आप देश की जनता का भरोसा नहीं जीत सकते।"

इसके जवाब में कांग्रेस ने गृह मंत्री से पूरे मामले का ब्योरा देने की मांग की।

रमेश ने लिखा, "सौ करोड़ भारतीयों को एसआईआर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। उन्हें इसके नतीजों के बारे में जानने का पूरा अधिकार है।"

उन्होंने कहा, "सच्चाई यह है कि "शाह इन्स्टीगेटेड रिमूवल" (एसआईआर) के सूत्रधार बार-बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर, असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की हताश जोड़ी ने करीब 14 करोड़ भारतीयों को वोट देने के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया है।"

रमेश ने आगे कहा, "क्या गृह मंत्री यह कहना चाहते हैं कि ये 14 करोड़ भारतीय घुसपैठिए हैं? क्या गृह मंत्री के रूप में उनकी असावधानी से देश में घुसपैठियों की संख्या में इतनी भारी बढ़ोतरी हुई है?"

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी तरह हमला बोला।

खड़गे ने लिखा, "गृह मंत्री द्वारा एसआईआर से बाहर किये गए 13.3 करोड़ भारतीयों को 'घुसपैठिया' बताना भारतीयता का अपमान है।"

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कांग्रेस ने पूछा, कितने घुसपैठियों की पहचान हुई, कितनों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और कितने घुसपैठियों को देश से बाहर भेजा गया है?
- शाह ने दावा किया कि 2029 का चुनाव भी एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा।
- कांग्रेस ने 14 करोड़ भारतीयों को एसआईआर द्वारा वोटर लिस्ट से हटाने की आलोचना की और पूछा, क्या गृह मंत्री यह कहना चाहते हैं कि 14 करोड़ भारतीय घुसपैठिए हैं।

नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान व साहिल को मृत्युदंड

मेरठ, 14 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बुधवार को जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को फांसी की सजा सुनाई। लगभग 13 माह चली इस सुनवाई में 22 गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया। अपने गुनाहों की सजा पाये जाने पर दोनों की आंखों में आंसू आ गए।

जिला कारागार से बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों की पेशी हुई। कोर्ट ने सजा सुनाने से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- मेरठ के इस चर्चित हत्यांकांड की सुनवाई 13 माह चली।

विचार बिन्दु

मन की प्रसन्नता से समस्त मानसिक और शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। –रामदास

पेंशन स्थगित वेतन है, सरकार की कृपा नहीं!

पेंशन किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार अथवा नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला दान, अनुदान या उपकार नहीं है। यह उसके जीवनभर की सेवाओं के बदले मिलने वाले वेतन का वह हिस्सा है, जिसका भुगतान सेवा अवधि में न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसलिए पेंशन को 'स्थगित वेतन' कहना पूरी तरह तर्कसंगत है। कर्मचारी अपनी युवावस्था और जीवन के सर्वाधिक उत्पादक वर्ष संस्थान को समर्पित करता है। उसके परिश्रम, अनुभव और सेवाओं से संस्थान तथा समाज लाभान्वित होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के माध्यम से उसे उसी अर्जित अधिकार का लाभ मिलता है। ऐसे में पेंशन का भुगतान रोकना केवल आर्थिक कठिनाई पैदा करना नहीं, बल्कि कर्मचारी के वर्षों के परिश्रम के प्रतिफल को अनिश्चितता में डालना है।

सेवा के बदले अधिकार, दया की अपेक्षा नहीं

जब कोई कर्मचारी सरकारी अथवा सार्वजनिक संस्थान में नियुक्त होता है, तब वह निर्धारित सेवा शर्तों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। वह नियमित रूप से कार्य करता है, अपने वेतन पर करों का भुगतान करता है और संस्थान के विकास में योगदान देता है। अनेक कर्मचारी पदोन्नति, स्थानांतरण तथा अन्य सेवा संबंधी परिस्थितियों के बीच अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सेवानिवृत्ति तक सेवा करते हैं। पेंशन इसी दीर्घकालीन सेवा व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

यदि कर्मचारी को यह विश्वास ही न हो कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे समय पर पेंशन मिलेगी, तो सामाजिक सुरक्षा की पूरी अवधारणा कमजोर हो जाती है। वृद्धावस्था में नियमित आय का सबसे विश्वसनीय साधन पेंशन है। इसी से भोजन, दवाइयों, आवास, बिजली-पानी और अन्य आवश्यक खर्चों की पूर्ति होती है। बढ़ती महँगाई तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के कारण वृद्धावस्था में नियमित आय का महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

पेंशनभोगी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना काम किए सरकार से धन माँग रहा हो। उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सेवा में लगाया है और पेंशन उसी सेवा का अर्जित प्रतिफल है। इसलिए पेंशन को सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ बताना उन कर्मचारियों के योगदान की उपेक्षा करना है, जिनकी मेहनत से प्रशासन, शिक्षा, अनुसंधान और सार्वजनिक सेवाओं का संचालन हुआ है।

न्यायपालिका ने भी माना पेंशन का महत्त्व

भारत में पेंशन के अधिकार को लेकर न्यायपालिका ने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय नेडी. एस. नकारा बनाम भारत संघ (1982)के ऐतिहासिक निर्णय में पेंशन को महज नियोक्ता की कृपा न मानते हुए सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था से जोड़ा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पेंशनभोगियों के साथ व्यवहार करते समय संवैधानिक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि प्रत्येक पेंशन विवाद का निर्णय संबंधित सेवा नियमों, लागू कानूनों और तथ्यों के आधार पर होता है। फिर भी न्यायिक दृष्टिकोण का व्यापक संदेश स्पष्ट है-पेंशनभोगियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या में गरिमापूर्ण जीवन का महत्त्व स्वीकार किया गया है। वहीं अनुच्छेद 14 समानता के सिद्धांत की रक्षा करता है। पेंशन संबंधी प्रत्येक मामले में इन प्रावधानों का अनुप्रयोग उसके तथ्यों और कानून के अनुसार होगा, लेकिन राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति न्यायसंगत तथा संवेदनशील व्यवहार करे।

राजस्थान के विश्वविद्यालयों के पेंशनभोगियों की पीड़ा

पेंशन के सिद्धांत की वास्तविक परीक्षा तब होती है, जब किसी संस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी अर्जित पेंशन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़े। राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के पेंशनभोगियों की स्थिति इस समस्या का गंभीर उदाहरण है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर सहित राज्य के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर लंबे समय से कठिनाइयाँ सामने आती रही हैं।

इन विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने कृषि शिक्षा, अनुसंधान, प्रसार और किसानों की समस्याओं के समाधान मी अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। कृषि वैज्ञानिकों ने नई तकनीकों के विकास, फसल उत्पादन बढ़ाने, मृदा स्वास्थ्य सुधारने और किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुँचाने के लिए दशकों तक काम किया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों ने संस्थानों के संचालन में योगदान दिया। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद यदि इन्हीं कर्मचारियों को पेंशन के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, तो यह व्यवस्था की गंभीर विफलता है।

जय नारायण विश्व विद्यालय, जोधपुर के पेंशनर को छह माह से पेंशन नहीं मिलने के कारण संघर्षरत है सभी पेंशनर विशेष रूप से पारिवारिक पेंशनर सबसे अधिक पीड़ित है और गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार एवं राजनीतिक प्रतिनिधि मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि विश्वविद्यालय के शिक्षक कोई महत्वपूर्ण वोट बैंक नहीं है। परन्तु राज्य सरकार को समझना होगा कि पेंशनरों को नियमित पेंशन का भुगतान करना सरकार का वैद्यानिक दायित्व है।

पेंशनभोगी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना काम किए सरकार से धन माँग रहा हो। उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सेवा में लगाया है और पेंशन उसी सेवा का अर्जित प्रतिफल है। इसलिए पेंशन को सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ बताना उन कर्मचारियों के योगदान की उपेक्षा करना है, जिनकी मेहनत से प्रशासन, शिक्षा, अनुसंधान और सार्वजनिक सेवाओं का संचालन हुआ है।

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का हवाला देकर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती। दूसरी ओर, विश्वविद्यालयों की सीमित आय का तर्क देकर पेंशनभोगियों को भुगतान से वंचित रखना भी न्यायोचित समाधान नहीं है। जब किसी विश्वविद्यालय की आय नियमित पेंशन भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है, तो राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को मिलकर स्थायी वित्तीय व्यवस्था बनानी चाहिए।

यह समस्या केवल लेखा-जोखा अथवा प्रशासनिक प्रक्रिया का विषय नहीं है। इसके पीछे हजारों परिवारों की आजीविका, सम्मान और भविष्य जुड़ा हुआ है। पेंशन में देरी का अर्थ है दवाइयों में कटौती, आवश्यक खर्चों में कमी और वृद्धावस्था में मानसिक तनाव। जिन लोगों ने जीवनभर संस्थान की सेवा की, उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़े, यह किसी भी कल्याणकारी व्यवस्था के लिए चिंताजनक स्थिति है।

समाधान के लिए ठोस कदम जरूरी

इस समस्या का स्थायी समाधान केवल आश्वासन देने से नहीं होगा। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे।

पहला, राजस्थान सरकार को कृषि विश्वविद्यालयों के पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी और वित्तीय व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। विश्वविद्यालयों की वास्तविक आय, पेंशन देनदारियों और भविष्य की आवश्यकताओं का स्वतंत्र आकलन कराया जाए।

दूसरा, नियमित पेंशन भुगतान के लिए समर्पित पेंशन निधि अथवा अन्य विश्वसनीय वित्तीय व्यवस्था विकसित की जाए। राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों के बीच अनुदान, योगदान तथा भुगतान की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट हों, ताकि प्रत्येक माह पेंशन के लिए अनिश्चितता न रहे।

तीसरा, बकाया पेंशन, महँगाई राहत और अन्य स्वीकृत लाभों के भुगतान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना घोषित की जाए। पात्रता और लागू नियमों के अनुसार भुगतान की स्थिति सार्वजनिक की जाए तथा विलंब के कारणों की जवाबदेही तय हो।

चौथा, पेंशनभोगियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाए। शिकायत प्राप्त होने, दस्तावेज पूरे होने और निर्णय होने की समय-सीमा निर्धारित की जाए। वृद्ध पेंशनभोगियों को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से उलझाने से बचाया जाए।

पाँचवाँ, राज्य सरकार को सभी कृषि विश्वविद्यालयों की समस्याओं का संयुक्त अध्ययन कर समानता, वित्तीय स्थिरता और कानूनी दायित्वों पर आधारित दीर्घकालीन नीति तैयार करनी चाहिए। जहाँ न्यायालय के आदेश लागू हों, वहाँ उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जाए।

सरकार की विश्वसनीयता की कसौटी

किसी सरकार की संवेदनशीलता का आकलन केवल नई योजनाओं की घोषणाओं से नहीं किया जा सकता। यह भी देखना होगा कि वह उन नागरिकों और कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करती है, जिन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा में लगा दिया। पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान सरकार पर कोई अतिरिक्त कृपा नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में आवश्यक कदम है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि पेंशन को खर्च की ऐसी मद न माना जाए जिसे वित्तीय कठिनाई के समय टाला जा सकता है। पेंशन देनदारियों का अनुमान समय रहते लगाना, पर्याप्त धन की व्यवस्था करना और भुगतान नियमित रखना सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है। संस्थान की वित्तीय समस्याओं का समाधान पेंशनभोगियों की आजीविका को अनिश्चित बनाकर नहीं किया जाना चाहिए।

अंततः प्रश्न केवल पेंशन की राशि का नहीं, बल्कि उस विश्वास का है जिसके आधार पर कर्मचारी अपना पूरा जीवन संस्थान को समर्पित करता है। यदि सेवानिवृत्ति के बाद उसे अपनी अर्जित पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़े, तो सेवा व्यवस्था का भरोसा कमजोर होता है।

पेंशन कोई खैरात नहीं, जीवनभर की सेवा का प्रतिफल है। यह स्थगित वेतन है, जिसे समय पर लौटाना नियोक्ता का दायित्व है। राजस्थान सरकार और कृषि विश्वविद्यालयों को इस सिद्धांत को व्यवहार में उतारना चाहिए। पेंशनभोगियों को आश्वासन नहीं, नियमित भुगतान चाहिए; सहानुभूति के शब्द नहीं, उनके अधिकारों का सम्मान चाहिए। यही सामाजिक न्याय है और यही एक संवेदनशील, जवाबदेह तथा कल्याणकारी शासन की पहचान होनी चाहिए।

-अतिथि सम्पादक,
प्रोफेसर (डा.) पी. सी. कंठालिया
पूर्व विभागाध्यक्ष (मृदा विज्ञान) एवं मुख्य वैज्ञानिक
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

मतदाता सूची का शुद्धिकरण: सवाल चुनाव आयोग पर नहीं, व्यवस्था को बेहतर बनाने पर होना चाहिए



रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

देश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव आयोग से सवाल पूछना और उसकी कार्यप्रणाली की आलोचना करना पूरी तरह जायज है, लेकिन क्या मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसी सामान्य और आवश्यक प्रक्रिया को ही राजनीतिक विवाद का विषय बना देना उचित है? इस पूरे विषय को समझने के लिए हमें कुछ व्यावहारिक सवालों पर ध्यान देना होगा।

क्या पिछले 20-25 वर्षों में देश में लोगों की मृत्यु नहीं हुई? क्या नए मतदाता पैदा नहीं हुए? क्या लोगों ने अपने शहर और राज्य नहीं बदले? क्या महिलाओं की शादी के बाद उनका निवास स्थान नहीं बदलता? क्या बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाते? क्या सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लगातार तबादले नहीं होते?

इन सवालों का जवाब स्पष्ट है। देश में करोड़ों लोग पिछले कुछ दशकों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं। ऐसे में यदि मतदाता सूची में पुराने पते पर नाम बने रह जाते हैं या किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हो जाता है, तो इसका समाधान मतदाता सूची को शुद्ध करना ही है।

कुछ सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई चर्चा में इस समस्या का एक दिलचस्प और व्यावहारिक उदाहरण सामने आया। सरकारी अधिकारियों की सेवा में दो-तीन या चार वर्ष में तबादले होना सामान्य बात रही है। कोई अधिकारी जोधपुर में रहा, फिर उदयपुर चला गया, उसके बाद अजमेर, बीकानेर या जयपुर जैसे किसी दूसरे शहर में पदस्थापित हो गया। इसी तरह केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों का कैडर या कार्यस्थल भी बदल सकता है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग शहरों में विभागीय कॉलोनियां होती हैं। किसी जगह सिविल लाइंस, किसी अन्य सरकारी विभागों की कॉलोनियां होती हैं। जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया होती थी, तब इन कॉलोनियों में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम स्थानीय मतदाता सूची में दर्ज हो जाते थे। समस्या यह है कि बाद में जब अधिकारी का तबादला हो गया, तो पुराने स्थान की मतदाता सूची से नाम हटना हमेशा उतनी आसानी से नहीं हुआ।

मतदाता सूची में पुराने नाम बने रहने का एक बड़ा कारण महिलाओं का विवाह के बाद स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। एक महिला विवाह से पहले अपने माता-पिता के शहर में रहती है। विवाह के बाद उसका स्थायी या सामान्य निवास किसी दूसरे शहर या राज्य में हो सकता है। ऐसी स्थिति में पुराने स्थान की मतदाता सूची से नाम हटाकर नए स्थान पर नाम दर्ज करवाना आवश्यक है।

इसी तरह हजारों-लाखों परिवारों में बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं। कुछ लोग कुछ वर्षों के लिए दूसरे शहर में रहते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। कुछ लोग स्थायी रूप से वहीं बस जाते हैं।

मतदाता सूची से जुड़े पुराने रिकॉर्ड की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसी व्यक्ति का पुराना नाम हमेशा अपने आप समाप्त नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर चला गया और उसने नए स्थान पर नाम दर्ज करा लिया, लेकिन पुराने स्थान की सूची से नाम नहीं हटवाया, तो दोनों जगह रिकॉर्ड मौजूद रह सकता है। एक व्यक्तिगत उदाहरण इसी समस्या को और स्पष्ट करता है। संबंधित व्यक्ति ने अलग-अलग स्थानों पर दर्ज अपने नामों को बाद में हटवाने की कोशिश की और पाया कि पुराने रिकॉर्ड कई स्थानों पर अभी भी मौजूद थे। इस तरह की स्थिति को केवल राजनीतिक दृष्टि से देखने के बजाय प्रशासनिक और तकनीकी समस्या के रूप में देखना ज्यादा उपयोगी होगा।

यदि किसी मतदाता सूची में पुराने, मृत, स्थानांतरित या दोहराए गए नाम मौजूद हैं, तो उनका सत्यापन और सुधार होना चाहिए। इसे लोकतंत्र के खिलाफ प्रक्रिया मानने के बजाय मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। इसे व्यापक स्तर पर मतदाता सूची के पुराने रिकॉर्ड की खामियों को उजागर करने और शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखने की बात कही गई है।

लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण सवाल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी उठता है। यदि किसी नागरिक को अपना नाम हटवाने, पता बदलवाने या नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने में वर्षों लग जाएं, तो नागरिकों का व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित होना स्वाभाविक है।

लेखक ने स्वयं दो साल पहले नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आवेदन किया था, लेकिन प्राप्ति का इंतज़ार अभी बाकी है। यही वह क्षेत्र है जहां चुनाव आयोग को तकनीक का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करना चाहिए। चुनाव आयोग को भी तकनीकी युग के साथ आगे बढ़ना होगा

आज जब बैंकिंग, रेलवे, पासपोर्ट और आयकर जैसी सेवाएं डिजिटल हो चुकी हैं, तो मतदाता सूची की प्रक्रिया भी आधुनिक, सरल और त्वरित होनी चाहिए। जैसे आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से सुविधाएं मिलती हैं, वैसे ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी चाहिए।

नागरिक अपने नाम, पते और मतदाता स्थिति की जानकारी ऑनलाइन देख सकें तथा आवश्यक सुधार के लिए आवेदन कर सकें। कानून और गोपनीयता का ध्यान रखते हुए विभिन्न सरकारी रिकॉर्ड के बीच बेहतर तकनीकी समन्वय से एक व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर दर्ज रहने की समस्या भी कम की जा सकती है। इसके लिए चुनावी और प्रशासनिक व्यवस्था को लगातार तकनीकी रूप से अपडेट करना होगा।

चुनाव आयोग की आलोचना तथ्यों के आधार पर हो और आयोग से पारदर्शिता, जवाबदेही तथा बेहतर तकनीकी व्यवस्था की मांग की जानी चाहिए। लेकिन मतदाता सूची में वास्तविक समस्याएं हैं तो केवल राजनीतिक विवाद के कारण उनके पुनरीक्षण को रोकना समाधान नहीं है। बेहतर व्यवस्था यह होगी कि मतदाता सूची का नियमित और पारदर्शी पुनरीक्षण हो, नागरिकों को पर्याप्त समय मिले, दावे-आपत्तियों की सरल ऑनलाइन व्यवस्था हो और किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलती से हटने पर प्रभावी अपील का अवसर उपलब्ध हो।

एक व्यावहारिक सुझाव यह है कि मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में हो। इसके बीच नागरिकों को स्थान परिवर्तन, मृत्यु, विवाह, नए मतदाता बनने या अन्य आवश्यक सुधारों की जानकारी आसानी से ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा मिले। मतदाता सूची को सही रखना केवल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिक और प्रशासन की साझा जिम्मेदारी है। आयोग को प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनानी होगी, वहीं नागरिकों को भी अपने मतदाता रिकॉर्ड को सही रखने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि मतदाता सूची सटीक हो, वास्तविक मतदाता उसमें दर्ज हों और पुराने या गलत रिकॉर्ड समय पर सुधारे जाएं। इसलिए पुनरीक्षण को राजनीतिक विवाद का विषय बनाने के बजाय इसे मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण क्यों हो रहा है। सवाल यह होना चाहिए कि इसे और अधिक पारदर्शी, सटीक और विश्वसनीय कैसे बनाया जाए।

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

संवैधानिक नैतिकता चौराहे पर-न्यायिक औचित्य, संस्थागत विश्वास और विधि का शासन



सूर्य प्रताप सिंह राजावत

सर्वोच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश द्वारा ऐसे विषय पर टिप्पणी करना, जो उनके समक्ष विचाराधीन नहीं है-क्या यह न्यायिक औचित्य की सीमाओं के भीतर आता है? क्या यह न्यायिक आत्म-संयम के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है? क्या यह संवैधानिक नैतिकता के एक मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है? यहाँ न्यायिक दृष्टांत के सिद्धांत पर चर्चा करना प्रासंगिक है। संविधान पीठ ने 1965 1767 के मामले में कहा था-इस बात पर बल देने की आवश्यकता शायद ही हो कि न्यायिक औचित्य और शिष्टाचार की दृष्टि से यह आवश्यक है कि यदि किसी मामले की सुनवाई कर रहे विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मत हो कि उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों-चाहे वे खंडपीठ के हों या एकल न्यायाधीश के-पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है, तो उन्हें एकल न्यायाधीश के रूप में बैठकर उस प्रश्न की जाँच प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, बल्कि मामले को खंडपीठ के समक्ष भेजना चाहिए या, उचित मामले में, संबंधित अभिलेख मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि वे इस प्रश्न की जाँच के लिए एक बड़ी पीठ का गठन कर सकें। ऐसे मामलों से निपटने का यही उचित और पारंपरिक तरीका है तथा यह न्यायिक शिष्टाचार और औचित्य के स्वस्थ सिद्धांतों पर आधारित है। अतः न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां द्वारा की गई टिप्पणियाँ न्यायिक अनुचितता की सीमा के निकट आती हुई प्रतीत होती हैं। यह कहा जा सकता है कि न्यायमूर्ति भुइयां को भारत के संविधान के अधीन उन्हें दिलाई गई शपथ की याद दिलाए जाने की आवश्यकता है।

अब सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकुर तथा अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की प्रतिक्रिया पर विचार कीजिए, जिन्होंने निर्वाचन आयोग के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच के लिए एक आयोग का गठन किया है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि जब यही विषय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को अंतरिम उपाय के लिए कोई पर्याप्त आधार संतोषजनक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है, तब उसी विषय-वस्तु पर एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा आयोग का नेतृत्व किया जाना ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने न्यायिक संयम और न्यायिक औचित्य की उपेक्षा की हो।

यह न्यायपालिका की संस्था के प्रति अविश्वास के मत के समान प्रतीत होता है। उपर्युक्त स्थिति उन व्यक्तियों द्वारा विधि के शासन के प्रति अविश्वास की आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है, जो स्वयं न्यायिक बिरादरी का हिस्सा रहे हैं। एक कार्यरत न्यायाधीश हैं और दूसरे एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश। यह कहा जा सकता है कि दोनों न्यायाधीशों के आचरण से उनकी गरिमा प्रभावित हुई है और न्यायपालिका के प्रति, तथा न केवल सर्वोच्च न्यायालय बल्कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के प्रति भी, जनता के विश्वास को आघात पहुँचाने का प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस चर्चा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मीडिया की भूमिका का उल्लेख किए बिना बात अधूरी रहेगी।

निर्वाचन आयोग के इस्तीफे की माँग भारत के संविधान के प्रति विश्वास में कमी, विधि के शासन में विश्वास के अभाव तथा न्यायपालिका में विश्वास की कमी की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को हटाने की उस संवैधानिक प्रक्रिया से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं, जो संवैधानिक ढाँचे के भीतर निर्धारित है और संवैधानिक पदाधिकारियों पर लागू सुरक्षा-व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है। यह लोकतंत्र के प्रति विश्वास की कमी का संकेत है और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है।

इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया को भी निर्वाचन आयोग से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों और मौखिक टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय की कार्यवाही का विवेकपूर्ण मूल्यांकन किए बिना, बार और बेंच के बीच हुई बातचीत को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है मानो वे न्यायालय के निष्कर्ष हों। किंतु यदि ऐसी टिप्पणियाँ न्यायिक आदेश में कहीं दर्ज नहीं हैं, तो उन्हें अंतिम न्यायिक निर्धारण के समान कानूनी पवित्रता प्राप्त नहीं होती और उन्हें न्यायिक रूप से अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र में विरोध के नाम पर और उपर्युक्त घटनाक्रम को देखते हुए, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और नौकरशाहों के एक समूह ने निर्वाचन आयोग पर किए जा रहे हमले की निंदा करते हुए एक पत्र लिखा है। यहाँ उन सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण और भूमिका को लेकर भी प्रश्न उठता है, जो निर्वाचन आयोग के समर्थन में सामने आए हैं।

जिस प्रकार शांति की नैतिकता और युद्ध की नैतिकता को समान नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के आचरण का मूल्यांकन भी उस परिस्थिति और संदर्भ के आधार पर किया जान चाहिए, जिसमें वे कार्य करते हैं। इसलिए, दूसरे समूह का स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने भारत में उपलब्ध चुनावी सुरक्षा उपायों का उल्लेख किया है, जिनमें मतदान केंद्रों पर मतदान एजेंटों की उपस्थिति, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से संबंधित उचित प्रश्नों का उत्तर देने की तत्परता, की सीलिंग और सुरक्षित अभिरक्षा, स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था तथा वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल प्रणाली के माध्यम से सत्यापन शामिल हैं। यह स्मरण रखना उचित है कि अच्छे लोगों की चुप्पी बुराई को अपने अनुचित उद्देश्यों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अतः उच्च सदुणों वाले लोगों को अपनी क्षमता के अनुपात में और संवैधानिक औचित्य की सीमाओं के भीतर संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करनी चाहिए।

मुझे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की वह बात स्मरण होती है, जिन्होंने 4 नवम्बर 1948 को कहा था कि भारत में संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है; इसे विकसित करना पड़ता है। इसके पश्चात्, 25 नवम्बर 1949 को उन्होंने संविधान सभा को सचेत करते हुए कहा कि भारत गणराज्य को तीन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम, नायक-पूजा को संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों की कीमत पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए। द्वितीय, सामाजिक लोकतंत्र को समानता और स्वतंत्रता के आधार-स्तम्भ के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। और, सबसे महत्वपूर्ण, भारत गणराज्य में गैर-संवैधानिक उपायों का सहारा लेने का कोई भी प्रयास, जिसमें ऐसे उपायों की तुलना गांधीजी के आंदोलनों से करना अथवा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार की तुलना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से करना शामिल है, भारत द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता की मूल भावना को समझने में एक गंभीर भूल होगी। अतः उनकी चेतावनी केवल राजनीतिक तरीकों तक सीमित नहीं थी; वह संवैधानिक लोकतंत्र और संवैधानिक तरीकों में आस्था को बनाए रखने के बारे में थी।

–सूर्य प्रताप सिंह राजावत,
अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर

श्री महाकाली मंदिर अखाड़ा डीडवाना, जहां स्वतः निकलती है फर्श से भभूत

मंत्र-मनीषियों के चिर साधना का मुख्य स्थान, पौराणिक आभानगरी (डीडवाना) के स्थापना काल में स्थापित महाकाली मंदिर अखाड़ा जन मानस के लिए अपार श्रद्धा का केंद्र है। आभा नगरी के मूल स्थापना स्थान सिंगी बास के पास से उस समय बहने वाली सरस्वती नदी के किनारे से सटे भाटी-बास में महायोगी गुरु गोरखनाथ के समय दो हजार से भी ज्यादा वर्षों से पहले स्थापित सिद्ध शक्ति स्थल नाथ योगियों, सिद्ध संतों व अनेक महात्माओं के द्वारा चमत्कारों का केंद्र रहा है। इस स्थल पर प्राप्त इतिहास में प्राणी मात्र को जगताप से हटा, योगामृत पिलाने व उन पर आने वाले घात प्रतिघात का प्रतिरोध करने वाला यह स्थान, अनेक गरिमाओं व महिमाओं से अलंकृत है। साबर साधना के रूप में जनमानस की सतत आस्थाओं से ओत-प्रोत,



इस मंदिर में अखंड शक्तियों के साक्षात प्रमाण मौजूद हैं।

विक्रम संवत 1016 में यहां औघड़ संत बिकाराम द्वारा साबर साधना के प्रभाव से 6 माह तक बिना अन्न जल गृहण किए सतत साधना करते रहने का प्रमाण हैं। उल्लेखनीय है कि अंतिम रूप से मंदिर की वर्तमान अर्चक पीढ़ी ने 17 मई 2001 को 18 जून 2013 को राजा गोपीचंद भरतरी को सिंह के साथ मंदिर परिसर में शाय काल में देखा है। परिसर में उनके नाम पर बने चबूतरे पर बैठने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। इसी पीढ़ी की एक महिला द्वारा अपने दिन तीन दिन के शिशु को कमर में बांधकर नगर में आए टीड्डी-दल को अपनी मंत्र शक्ति से घड़े में कैद कर नागोरी गेट में घड़े के धीरघने (मुंह) में से निकाला था। अंग्रेज अफसर को प्रभावित करने वाले इस कृत्य ने क्षेत्र में हजारों मण धान को भी नष्ट होने से बचाया था। जो बाद में किसानों का आस्था का केंद्र बन गया। साबर साधना के चमत्कारिक प्रमाण आज भी प्रत्यक्ष रूप में इस मंदिर में विद्यमान है। भूत प्रेत एवं अप्राकृतिक रूप से मनुष्य योनियों को सताने वाली आत्माएं रात्रि पूजन के समय मां काली से अपनी मुक्ति की याचना करती है। इन आत्माओं के साथ वर्तमान अर्चक के कई दुर्लभ चित्र है एवं इनका वैज्ञानिक आधार जानने के लिए शोध कर रहे हैं। इन चमत्कारों को यहां प्रमाण रूप में देखा जा सकता है, वह है, इसके मार्बल जड़ित आंगन में घृत व विभूति का निकलना। कहते हैं कि आंगन में निकली इस भभूति को लगाने से अनेक असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है।

राशिफल



पंडित अनिल शर्मा

गुरूवार 15 अक्टूबर, 2026

आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत-2083, ज्येष्ठा नक्षत्र शुक्रवार प्रातः 6:48 तक, सौभाग्य योग रात्रि 9:15 तक, बव करण दिन 2:20 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति- सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कर्क, बुध-तुला, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सि

मुक्तिधाम में पौधारोपण किया

कोटा, (निसं)। ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन के पदाधिकारी व सदस्यों द्वारा बुधवार को स्टेशन स्थित संजय गांधी मुक्तिधाम परिसर में पर्यावरण संरक्षण एवं गौसेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

फेडरेशन के अध्यक्ष जी.पी.सिंह एवं उपाध्यक्ष एम. एस.बग्गा के नेतृत्व में सदस्यों ने मुक्तिधाम में पूर्व में लगाए गए पौधों की देखभाल की, खराब हुए पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाए और वृक्षों की सिंचाई की।

प्रेस सचिव राजेश गौतम ने बताया कि इसके पश्चात सदस्यो ने मुक्तिधाम स्थित गौशाला में पहुंचकर गायों की देखभाल की और हरा चारा खिलाया।

इस मौके पर देव शर्मा, आर. के. अग्रवाल, हरीश खांडेकर, राजेश कपूर, अजय कपूर और मोहन सिंह सहित कई सदस्य मौजूद थे।

अवैध मादक पदार्थ 90 किलो डोडा-चूरा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। ग्रामीण इलाके की मंडाना पुलिस टीम ने मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए एक कार से अवैध मादक पदार्थ 90.320 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, टीम ने कार्यवाही करते हुए कार को जप्त किया है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये विशेष अभियान ऑपरेशन रूट क्लियरेंस चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि मंडाना थाने के थानाधिकारी सुमेर सिंह मय जाप्ता इलाके में गश्त व चेकिंग कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस टीम को मुखबीर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध कार गोपालपुरा टोल प्लाजा के समीप घुम

- मादक पदार्थ पंजाब ले जाया जा रहा था

रही है। उक्त सूचना पर थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और मुखबीर द्वारा बताई गई कार को देखकर पुलिस टीम ने कार चालक को रोकना चाहा तो कार चालक द्वारा तेज गति से कार को भगाकर ले जाने लगा।

ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम को संदेह होने पर टीम ने कार का पीछा किया और फाटाखेड़ा पुलिया के नीचे कार को रूकवाकर कार में बैठे लोगों से पूछताछ की गई कोई संतोषप्रद जबाव नही मिलने पर पुलिस टीम ने दोनो व्यक्तियो को डिटेन कर कार की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान कार मे अवैध मादक पदार्थ 90.320 किलोग्राम डोडा-चूरा बरामद किया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही में जप्त मादक पदार्थ व वाहन की कीमत करीब 25 लाख है।

पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ बरामद होने पर एनडीपीएस एक्ट मे कार्यवाही करते हुए जिला मलेरकोटला पंजाब के झुंडा निवासी वीरेन्द्र सिंह डिंडसा (45) एवं जिला मलेरकोटला पंजाब के हरनामा कॉलोनी अमरगढ़ निवासी अमरिन्दर सिंह (42) को गिरफ्तार किया, ग्रामीण एसपी ने बताया कि मामले में सामने आया कि अवैध मादक पदार्थ मध्यप्रदेश के मंदसौर से ग्रामीण क्षेत्र होते हुए पंजाब ले जाया जा रहा था, पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन के लिए विशेष शिविर लगाया

कोटा, (निसं)। रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा और सहायता की जिम्मेदारी निभाने वाले आरपीएफ कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन के लिए आरपीएफ रिजर्व लाइन में हार्टफुलनेस के सहयोग से विशेष शिविर आयोजित किया गया, शिविर में 51 आरपीएफ कर्मियों ने भाग लिया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्री सुरक्षा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में आरपीएफ कर्मियों के लिए मानसिक सतर्कता, धैर्य और एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नियमित ध्यान एवं योग का अभ्यास तनाव कम करने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। शिविर में हार्टफुलनेस के पुष्पेंद्र शर्मा ने कर्मचारियों को ध्यान एवं योग का अभ्यास कराते हुए तनाव प्रबंधन के सरल तरीके बताए।

रामलीला में धनुष यज्ञ, रावण-बाणासुर संवाद का मंचन

कोटा, (निसं)। रेलवे वर्कशॉप कॉलोनी स्थित शिव मंदिर परिसर में शिव मंडल विकास समिति द्वारा आयोजित 53वीं रामलीला के अंतर्गत बुधवार को धनुष यज्ञ, रावण-बाणासुर संवाद एवं लक्ष्मण-परशुराम संवाद का कलाकारों द्वारा बहुत ही सुंदर एवं प्रभावशाली मंचन किया गया। धनुष यज्ञ के दौरान प्रभु श्रीराम द्वारा धनुष तोड़ते ही पूरा पंडाल तालियों और जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। धनुष टूटने के बाद माता सीता ने प्रभु श्रीराम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण किया। इस प्रसंग का मंचन देखकर उपस्थित श्रद्धालु भावविभोर हो गए। इसके पश्चात भगवान परशुराम के क्रोधित होकर सभा में पहुंचने तथा लक्ष्मण-परशुराम संवाद का कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनय किया। दोनों के बीच हुए तीखे संवादों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रावण-बाणासुर संवाद का भी

- रामलीला में प्रतिदिन रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है

आकर्षक मंचन किया गया। शिव मंडल विकास समिति के अध्यक्ष प्रताप भान सिंह ने बताया कि रामलीला में प्रतिदिन रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है। आगामी कार्यक्रमों में राम विवाह, राम वनवास, निषादराज भेंट तथा केवट संवाद सहित अन्य प्रसंग प्रस्तुत किए जाएंगे। रामलीला का आयोजन 20 अक्टूबर तक प्रतिदिन रात्रि 8.30 बजे से शिव मंदिर, रेलवे वर्कशॉप कॉलोनी, कोटा जंक्शन पर किया जा रहा है। इसमें राधा सर्वेश्वरी रामलीला एवं रासलीला मंडली, वृंदावन-मथुरा के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं।

'नारी राष्ट्र गौरव युवती सम्मेलन' में नारी शक्ति का संदेश दिया

कोटा, (निसं)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की ओर से नारी राष्ट्र गौरव युवती सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में करीब 2,000 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। युवतियों की भारी उपस्थिति के बीच नारी शक्ति, भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।

एबीवीपी की महानगर मंत्री दीप्ति मेवाडा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कल्पना देवी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रो. विमला डुंकवाल तथा विशेष उपस्थिति के रूप में अभाविप की राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक प्रेरणा भारद्वाज एवं चित्तौड प्रांत की प्रांत सहमंत्री चेतना पांचाल उपस्थित रहीं। सम्मेलन का उद्देश्य युवतियों

- सम्मेलन में करीब 2,000 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की
- 'नारी समाज की आधारशिला है और राष्ट्र निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है'

में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान एवं सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के साथ भारतीय संस्कृति, संस्कार और नारी शक्ति के महत्व को उजागर करना है।

उन्होंने कहा कि नारी समाज की आधारशिला है और राष्ट्र निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। युवतियों को अपनी प्रतिभा एवं सामर्थ्य पहचानकर समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देना चाहिए। मुख्य अतिथि विधायक कल्पना देवी ने कहा कि नारी शक्ति भारतीय संस्कृति और समाज की सशक्त आधारशिला है। महिलाओं एवं युवतियों को शिक्षा, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए।

विशिष्ट अतिथि प्रो.विमला डुंकवाल ने कहा कि नारी शक्ति देश की प्रगति और समृद्धि का आधार है। अभाविप की राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक प्रेरणा भारद्वाज ने कहा कि नारी सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए समान अवसर और सही दिशा प्रदान करना है। प्रत्येक युवती में समाज को नई दिशा देने की क्षमता है।

रामपुरा की महारानी का मनमोहक श्रृंगार

कोटा, (निसं)। नवदुर्गा सेवा समिति, रामपुरा, कोटा के तत्वावधान में रामपुरा की महारानी का प्रतिदिन नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, आकर्षक परिधान, प्रतिदिन लगने वाला भोग और वहां आने वाले भक्तों का रैला थमने का नाम नहीं ले रहा है, प्रतिदिन संध्या आरती में सैकडों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। समिति के संरक्षक विश्वनाथ शर्मा, अमरनाथ शर्मा ने बताया कि कोटा ही नहीं दूरदराज से भी लोग दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। देर रात तक रामपुरा की महारानी के दर्शनों के लिए लोगों की कतारें लग रही है। महारानी का प्रतिदिन श्रृंगार हो रहा है, जिसमें गुजरात से डेकस आ रही है वहीं दिल्ली से इंग्लिश फूलों का हार आ रहा है। प्रतिदिन एक समय पांच किलो पुष्पहार पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां महिला मंडल की ओर से भजन गाए जा रहे हैं। पार्षद अमरनाथ शर्मा ने बताया कि सभी के सामूहिक प्रयासों ने रामपुरा की महारानी के विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रतिदिन कार्यक्रमों के माध्यम से माताराणी का गुणगान हो रहा है। आज गुरूवार को रात्रि 8.30 बजे सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। 16 अक्टूबर को महाआरती रात्रि 8 बजे होगी जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालू उपस्थित रहेंगे। वहीं 17 अक्टूबर को डांडिया रास का आयोजन होगा, जिसमें बालिकाएं शामिल होंगी और विजेताओं को नवाजा जाएगा। 20 अक्टूबर को माताराणी का विसर्जन सायं 6 बजे होगा, जिसमें धूमधाम से बैंड बाजों के साथ माताराणी को विसर्जन किया जाएगा। इसी दिन 2100 कन्याओं को भोजन कराया जाएगा और कार्यक्रम का समापन होगा।

ट्रैप शूटर नंदीका सिंह ने बरेटा शॉटगन गोल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता, कोटा का मान बढ़ाया

कोटा, (निसं)। दिल्ली स्थित डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में 8 से 13 अक्टूबर तक आयोजित प्रतिष्ठित बरेटा शॉटगन गोल्ड कप में कोटा की बेटी और प्रतिभावान ट्रैप शूटर नंदीका सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।

विश्व विख्यात कंपनी बरेटा की 500वीं वर्षगांठ के अवसर पर नेशनल राईफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश-विदेश के 300 से अधिक शीर्ष अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शॉटगन शूटर्स ने हिस्सा लिया था। सीनियर वुमेन ट्रैप शूटिंग कैटेगरी में कड़े मुकाबले के बीच नंदीका ने कई दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए यह शीर्ष उपलब्धि हासिल की। नंदीका के पिता एवं कोच अशोक पाल सिंह ने जानकारी दी कि इसी वर्ष नंदीका ने ट्रैप शूटिंग में स्टेट चैंपियन का खिताब जीतने के अलावा 'ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन' में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था।

शॉटगन शूटिंग में यह उनका मात्र तीसरा वर्ष है, जबकि इससे पहले वह पिस्टल शूटिंग में भी कई पदक जीत चुकी हैं। अब तक वह राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 20 से अधिक पदक जीतकर कोटा और राजस्थान का नाम रोशन कर चुकी हैं। अशोक पाल सिंह ने बताया कि शॉटगन शूटिंग एक बेहद खर्चीला और चुनौतीपूर्ण खेल है, जिसमें सफलता के लिए अत्यधिक मानसिक एकाग्रता और निरंतर की अभ्यास की आवश्यकता होती है। मात्र तीन साल के अल्प समय में शीर्ष स्तर पर पहुंचने वाली नंदीका का मुख्य लक्ष्य देश के लिए ओलंपिक का पहला महिला ट्रैप शूटिंग गोल्ड मेडल जीतना है।

इस शानदार सफलता का श्रेय शॉटगन कोच केसरी सिंह नाचना के विशेष मार्गदर्शन तथा कोटा जिला प्रशासन एवं जिला कलेक्टर कार्यालय से समय-समय पर मिले सहयोग को जाता है। जिसके चलते उन्हें अपने खेल को निखारने में अभूतपूर्व सहायता मिली। नंदीका की इस ऐतिहासिक जीत पर खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों ने शुभकामनाएं दी है।

अग्निशमन कार्मिकों को मूल पद पर लगाने की मांग

छबड़ा (निसं)। दीपावली पर आगजनी की घटनाओं से निपटने और आमजन की सुरक्षा को लेकर छबड़ा नगरपालिका के अग्निशमन कार्मिकों को उनके मूल पद पर लगाने की मांग उठी है। कार्मिकों का कहना है कि फायरमैन जैसे आपातकालीन सेवा से जुड़े कर्मचारियों को अन्य शाखाओं में लिपिकीय एवं गैर अग्निशमन कार्यों में लगाने से जरूरत के समय अग्निशमन सेवाएं प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाते हुए सभी अग्निशमन कार्मिकों को मूल कार्य की जिम्मेदारी सौंपने की मांग की गई है।

अग्निशमन कार्मिक रवि यादव, सत्यप्रकाश मेघवाल, गिर्राज नागर, सुरेंद्र और नरेश सांखला ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से 30 सितंबर 2026 को जारी आदेश में राज्य के नगर निकायों में कार्यरत प्रशिक्षित एवं डिप्लोमाधारी फायरमैन की सेवाएं उनके मूल अग्निशमन कार्यों में लेने तथा उनसे नियमित रूप से गैर अग्निशमन एवं लिपिकीय कार्य नहीं करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद यहां की नगरपालिका में अग्निशमन कार्मिकों से विभिन्न शाखाओं में कार्य करवाया जा रहा है। कार्मिकों ने बताया कि दीपावली के दौरान आगजनी की घटनाओं की आशंका को देखते हुए अग्निशमन दल का हर समय तैयार रहना आवश्यक है। यदि अग्निशमन कार्मिक अन्य कार्यों में लगे रहेंगे तो आपात स्थिति में घटनास्थल पर समय पर पहुंचने में परेशानी हो सकती है। इससे जनहानि और धनहानि का जोखिम बढ़ने की आशंका बनी रहती है। इस मामले में निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर नगरपालिका के सभी अग्निशमन कार्मिकों को उनके मूल पद पर पदस्थापित करने की मांग की गई है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण का लाभ उठाया है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, उनके ऋण को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी लागू होगा।

क्रमांक	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	सैक्शन 13 (2) के नोटिस तिथि	सैक्शन 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	87564169 और 151689042	गृह ऋण	26 सितंबर 2026	9,64,104.41/-

ऋणग्रहिताओं एवं सह ऋणग्रहिताओं का नामः 1. रामनिवास नगर, 2. धन्नालाल नगर, 3. मोहनी बाई

सम्पत्ति पता- पट्टा संख्या 13 के साथ प्लॉट का वह पूरा टुकडा और पार्सल, प्लॉट क्षेत्र 45 x 40 = 1800 वर्ग फीट, खसरा संख्या 201 पर स्थित ग्राम-पिपिल्या जागीर, ग्राम पंचायत-खोपर, पंचायत समिति-छाबडा, जिला-बारां, राजस्थान-325220 और इसकी सीमाएं-पूर्व-नानीबाई पत्नी बाबू खान का मकान, पश्चिम-घर का प्रवेश द्वार, उत्तर-जगदीश पुत्र बद्रीलाल नगर, दक्षिण-सुरेशचंद पुत्र हीरालाल नगर

आपसे कहा जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तारीखों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, प्रभारों आदि के साथ इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ एसएआरएफईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री/पट्टे या अन्यथा रूप से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
दिनांक- 15.10.2026 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित
स्थान- राजस्थान और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)



कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 153 दिनांक : 13.10.26

नाम हस्तांतरण वाहने बाबत् आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा दुकान/भूखण्ड संख्या-23 रंग विहार आवासीय योजना का आवंटन/नामहस्तारण क्रमांक 253 दिनांक 03.08.1996 को श्रीमति कमला तिवारी पत्नि श्री कल्याण प्रसाद तिवारी को जारी किया गया। श्री कमला तिवारी की मृत्यु दिनांक 09.04.2016 को मृत्यु हो जाने के उपरांत विधिक वारिसान/वसीयत/हक त्याग (रिलीज डीड) के आधार पर श्री कौशल किशोर दीक्षित पुत्र स्व. श्री राम निवास दीक्षित द्वारा उक्त भूखण्ड/दुकान को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/दुकान संख्या- 23 रंग विहार आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्री कौशल किशोर दीक्षित पुत्र स्व. श्री राम निवास दीक्षित के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11 विक्रय/2026/59 दिनांक : 14.10.2026

नाम हस्तातंरण वाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 26 गुमानपुरा थाने के पीछे व्यावसायिक योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 76 दिनांक 19.11.1992 को एन.ए. बद्रर्स प्रो. श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री वी.पी. अग्रवाल के नाम आवंटन किया गया था। एन.ए. बद्रर्स प्रो. श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री वी.पी. अग्रवाल द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री सैफुद्दीन पुत्र श्री हाजी मुल्ला एजाज हुसैन रंगवाला द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2002 को श्री अब्बास हुसैन पुत्र श्री हाजी मुल्ला एजाज हुसैन को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्री अब्बास हुसैन पुत्र श्री हाजी मुल्ला एजाज हुसैन द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 26 गुमानपुरा थाने के पीछे व्यावसायिक योजना का नाम हस्तान्तरण श्री अब्बास हुसैन पुत्र श्री हाजी मुल्ला एजाज हुसैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 154 दिनांक : 13.10.26

नाम हस्तातंरण वाहने बाबत् आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा की सुभाष नगर आवासीय योजना के भूखंण्ड/आवास संख्या 906 का आवंटन/विक्रय/ हस्तान्तरण/रजि. प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 479 दिनांक 05.03.2021 को श्री अंकुर खुराना पुत्र श्री सतपाल खुराना को आवंटन/ नामांतरण/रजि. किया गया था। आवंटी श्री अंकुर खुराना द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का मुख्तारआम श्री नरेश अग्रवाल पुत्र श्री ज्ञानचंद को कर दिया गया। मुख्तारआम द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.08.2026 को श्री निर्मल नागर पुत्र श्री दुर्गाशंकर नागर को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाब गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 906 योजना सुभाष नगर आवासीय का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्री निर्मल नागर पुत्र श्री दुर्याशंकर नागर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/1328 दिनांक : 14.10.2026

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रंगबाड़ी योजना ''गुलाबबाड़ी'' खसरा नं. 164 में स्थित भूखण्ड संख्या 11 का पश्चिमी भाग के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदक/आवेदिका श्री अंशुमन अग्रवाल पुत्र श्री गिर्राज अग्रवाल निवासी - 3/399, स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 578 दिनांक 02-10-2021 को श्री गिर्राज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सूरजमल अग्रवाल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार मृत्यु दिनांक 03.07.2025 को हो चुकी है। पट्टेधारी द्वारा अपने जीवनकाल में जर्ये रजि. वसीयतनामा दिनांक 12.08.2025 से आवेदक के पक्ष मे किया गया है। इस वसीयतनामा के आधार पर आवेदक द्वारा भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्री अंशुमन अग्रवाल पुत्र श्री गिर्राज अग्रवाल के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज.)

क्रमांक-ननिको/भ.नि.अनु./2026/25041929 दिनांक- 14.10.2026

भू-उपयोग परिवर्तन बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री लोकेन्द्र जैन पुत्र श्री खुबचन्द एवं श्रीमती शालिनी जैन पत्नी श्री लोकेन्द्र जैन निवासी 16 यू.आई.टी स्कीम अम्बेडकर नगर सकतपुरा कोटा (राज.) द्वारा भूखण्ड संख्या- 584-ए, तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण नगर निगम कोटा के कार्यालय आदेश क्रमांक 1623-24 दिनांक 16.06.2020 से श्री लोकेन्द्र जैन पुत्र श्री खुबचन्द एवं श्रीमती शालिनी जैन पत्नी श्री लोकेन्द्र जैन के पक्ष में नामातंरण किया गया है। आवेदित भूखण्ड का भू उपयोग कोटा शहर के अनुमोदित मास्टर/ मास्टर / जोनल प्लान व प्रचलित नियमों के दृष्टिगत मिश्रित प्रयोजनार्थ निर्धारित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा में उक्त भूखण्ड 584-ए. तलवण्ड़ी कोटा क्षेत्रफल- 4500 वर्गफुट का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार भूखण्ड के आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन बाबत किसी व्यक्ति / संस्था आदि या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता हो, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस की अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा कार्यालय में प्रस्तुत करे। मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज.)

क्रमांक-ननिको/भ.नि.अनु./2026/25041994 दिनांक- 14.10.2026

भू-उपयोग परिवर्तन बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री लोकेन्द्र जैन पुत्र श्री खुबचन्द एवं श्रीमती शालिनी जैन पत्नी श्री लोकेन्द्र जैन निवासी 16 यू.आई.टी स्कीम अम्बेडकर नगर सकतपुरा कोटा (राज.) द्वारा भूखण्ड संख्या- 585-ए, तलवण्ड़ी कोटा क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट एवं भूखण्ड से लगी हुई भू-पट्टी क्षेत्रफल 333 वर्गफुट का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण नगर निगम कोटा के कार्यालय आदेश क्रमांक 8174-75 दिनांक 04.07.2018 से श्री लोकेन्द्र जैन पुत्र श्री खुबचन्द एवं श्रीमती शालिनी जैन पत्नी श्री लोकेन्द्र जैन के पक्ष में नामातंरण किया गया है। आवेदित भूखण्ड का भू उपयोग कोटा शहर के अनुमोदित मास्टर/जोनल प्लान व प्रचलित नियमों के दृष्टिगत मिश्रित प्रयोजनार्थ निर्धारित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा में उक्त भूखण्ड 585-ए, तलवण्ड़ी कोटा क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट एवं भूखण्ड से लगी हुई भू-पट्टी क्षेत्रफल 333 वर्गफुट का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार भूखण्ड के आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी व्यक्ति/ संस्

अतरसिंह भड़ाना हत्याकांड : करीब 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 65 नामजद

पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज की

- नामजद आरोपियों की धरपकड़ के लिए 25 से 30 पुलिस टीमों का गठन, अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है
- अतर सिंह भड़ाना और ग्रामीणों के बीच वर्षों से लीज को लेकर विवाद चल रहा था, ग्रामीण लीज संचालन का विरोध कर रहे थे : आईजी प्रीति चंद्रा

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर जिले के भौंडा गांव में पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता अतरसिंह भड़ाना की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है।

भरतपुर रेंज आईजी प्रीति चंद्रा के अनुसार, मामले में करीब 150 से 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें लगभग 65 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि अन्य लोगों की भूमिका को लेकर भी शिकायत में उल्लेख किया गया है। नामजद आरोपियों की धरपकड़ के लिए 25 से 30 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। वहीं, मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से चार भौंडा गांव के निवासी हैं। आईजी प्रीति चंद्रा ने बताया कि अतर सिंह भड़ाना और ग्रामीणों के बीच पिछले कई वर्षों से लीज को लेकर विवाद चल रहा था। ग्रामीण लीज संचालन का विरोध कर रहे थे। इस विवाद के संबंध में पहले भी पुलिस की ओर से पाबंदी की कार्रवाई की गई थी और मुकदमे दर्ज हुए थे। उन्होंने बताया कि जब भी भड़ाना पुलिस को फोन करते थे, पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंचती थी और वहां रुककर निगरानी भी करती थी। आईजी प्रीति चंद्रा ने कहा कि विवाद लंबे समय से चल रहा था, ऐसे में स्थानीय स्तर पर पुलिस को ग्रामीणों के बीच व्याप्त आक्रोश की जानकारी जुटानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बड़ी घटना की आशंका को लेकर स्थानीय स्तर पर खुफिया सूचना एकत्र करना जरूरी था। पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना ने क्या हत्या से पहले सुरक्षा की मांग की थी? इस सवाल पर प्रीति चंद्रा ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि भड़ाना ने सुरक्षा मांगी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लीज विवाद काफी समय से चल रहा था और ग्रामीण इसके संचालन के विरोध में थे।

घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को लेकर आईजी ने बताया कि कैमरों की डीवीआर परिवादी पक्ष अपने साथ ले गया है। पुलिस ने उनसे इस संबंध में जानकारी ली है। परिवादी पक्ष ने डीवीआर उपलब्ध कराने की बात कही है। डीवीआर मिलने के बाद फुटेज की जांच से घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। आईजी ने बताया कि घटना रात के अंधेरे में हुई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल एफआईआर में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा घटना में अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे, यह जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस की टीमें नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड के बाद पुलिस विभाग ने भी कार्रवाई की है। वैर थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एएसपी प्रेरणा शेखावत और भुसावर सीओ नीरज भारद्वाज को एपीओ कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों पर हुई कार्रवाई के संबंध में आईजी ने कहा कि लंबे समय से विवाद चलने के बावजूद स्थानीय स्तर पर संभावित तनाव और ग्रामीणों के आक्रोश की जानकारी पुलिस तक प्रभावी ढंग से पहुंचनी चाहिए थी। उन्होंने माना कि इस तरह की घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर आसूचना जुटाने की आवश्यकता थी।

ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाली गैंग का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

गैंग का सरगना हरियाणा के पुन्हाना का रहने वाला है, जो अभी फरार है

अलवर, (निसं)। साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दबिश देकर साइबर ठगी गैंग के आरोपी मूल खाताधारक नितेश कुमार (26) पुत्र हेमराज मेघवाल निवासी बीके बिरला इंस्टीट्यूट के पास पिलानी जिला झुंझुनूं व दूसरे आरोपी फर्जी बैंक खाता खुलवाकर साइबर ठगों को बेचने वाला विक्रम सिंह (25) पुत्र फूलचंद सैनी निवासी सिंघाना जिला झुंझुनूं को गिरफ्तार किया है। जबकि गैंग के सरगना हरियाणा के पुन्हाना के रहने वाला है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।

एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि जिले में ऑनलाइन ठगी, म्यूल अकाउंट, सेक्सटोर्शन और फर्जी सिम बेचने वाले गिरोह के खिलाफ विशेष साइबर संग्राम अभियान-3.0 चलाया जा रहा है। इसी के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने 15 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी के पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। फोन करने वाले ने खुद को परिचित बताते हुए कहा आपके पापा को पैसों की सख्त जरूरत है। आपके खाते में 3 हजार रुपए भेज रहा हूं। इसके तुरंत बाद ठग ने दोबारा कॉल कर झूठ बोला कि गलती से 3 हजार की जगह 30 हजार रुपए ट्रांसफर हो गए हैं और 27 हजार रुपए लौटाने की बात कही। बेटी आरोपी के झांसे में आ गई। इसके बाद ठग ने उसे अपनी बातों में उलझाकर टुकड़ों में कुल 91 हजार रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए।

एसपी ने बताया कि डीएसपी साइबर क्राइम वीरेंद्र सिंह भाटी के सुपरविजन में गठित टीम ने बैंक खातों की डिटेल खंगाली। तकनीकी अनुसंधान और साइबर सर्विलांस की मदद से संदिग्धों को चिह्नित कर दोनों पकड़ लिया। साइबर ठगी करने वाले गैंग के तार झुंझुनूं और हरियाणा के पुन्हाना से जुड़े होने का खुलासा हुआ है। आरोपी विक्रम सैनी चिड़ावा (झुंझुनूं) में ढाबा चलाता है। हरियाणा के पुन्हाना निवासी दो युवकों ने उसके ढाबे पर करीब 8-10 दिन लगातार खाना खाया और उससे जान-पहचान बढ़ा ली। ठगों ने ढाबा संचालक विक्रम को झूठ बोला कि वे यहां काम करने आए हैं और उनका बैंक खाता ब्लॉक हो गया है। उन्होंने 10 हजार रुपए देने का लालच देकर कहा कि उन्हें कुछ दिनों के लिए बैंक खाता किराए पर चाहिए। लालच में आकर ढाबा संचालक ने आरोपी नितेश मेघवाल के नाम से बैंक में खाता खुलवा दिया। इस म्यूल अकाउंट का एटीएम कार्ड और पासबुक पुन्हाना के ठगों को सौंप दिए गए। इसके बाद साइबर ठगों ने पीड़ित युवती से हड़पे गए 91 हजार रुपए इसी किराए के खाते में ट्रांसफर करवाए और रकम निकालकर फरार हो गए।

घर के बाहर बैठी महिला को ट्रैक्टर ने कुचला, मौत

सीकर, (निसं)। घर के बाहर बैठी महिला को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला का चार साल का पोता और नौ महीने की पोती भी वहीं बैठे थे। उनको हल्की चोट आई है।

घटना उद्योग नगर थाना इलाके में पिपराली चौराहे के पास धन्वंतरि हॉस्पिटल के नजदीक मंगलवार रात करीब आठ बजे की है। टक्कर से घर की दीवार भी टूट गई। घटना के बाद ड्राइवर पिपराली चौराहे के पास ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। बुधवार सुबह परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर करीब दो घंटे तक धरना दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार पिपराली चौराहे के पास रहने वाली बानो (45) पत्नी जब्बार मंगलवार रात पोते कबीर और पोती गुड़िया के साथ घर के बाहर चबूतरे पर बैठी हुई थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में एक ट्रैक्टर बानो की तरफ आया और टक्कर मारते हुए दीवार तोड़ दी। परिजन बानो को एसके हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कबीर और गुड़िया को हल्की चोट आई है। परिजन बुधवार सुबह हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।

जमीन हड़पने के मामले में जैसलमेर से गिरफ्तार आरोपी की जोधपुर में मौत

- मंगलवार को आरोपी की रिमाण्ड अवधि में तबीयत बिगड़ने के बाद जैसलमेर से जोधपुर रैफर किया था, बुधवार सुबह आरोपी की जोधपुर में उपचार के बीच मौत हो गई, शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया

जोधपुर, (कासं)। जैसलमेर जिला पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी प्रकरण में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया। मंगलवार को उसकी रिमाण्ड अवधि में तबीयत बिगड़ने के बाद जैसलमेर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जोधपुर रैफर कर दिया गया। बुधवार सुबह उसकी यहां जोधपुर में उपचार के बीच मौत हो गई। फिलहाल शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस की तरफ से अग्रिम अनुसंधान जारी है।

आरंभिक पड़ताल में मृतक की पहचान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी नरेश कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसलमेर जिले के शहर कोतवाल प्रेमाराम विश्नोई के अनुसार कोतवाली थाने में नरेश कुमार के खिलाफ 7 जुलाई को मामला दर्ज हुआ था। परिवादी ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने धोखाधड़ी कर पोंग बांध विस्थापित को आवंटित की गई कीमती जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़पने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने 12 अक्टूबर को नरेश कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 13 अक्टूबर को उसे अदालत में पेश किया गया। जहां से न्यायालय ने आरोपी का पुलिस रिमांड मंजूर किया था। पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर की रात करीब 8.15 बजे पूछताछ के समय नरेश कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसने सीने और पेट में तेज दर्द होने की शिकायत की। स्थिति गंभीर होने पर पुलिसकर्मी उसे तुरंत राजकीय जवाहिर अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे 108 एंबुलेंस से जोधपुर रैफर कर दिया। नरेश कुमार का जोधपुर के मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल में इलाज चल रहा था। बुधवार की सुबह करीब 5.45 बजे इलाज के बीच उसकी मौत हो गई। पुलिस की तरफ से अब अग्रिम जांच की जा रही है।

भोपालगढ़ में पिकअप की टक्कर से युवक की मौत

जोधपुर, (कासं)। जिले के ग्रामीण क्षेत्र भोपालगढ़ में बुधवार की सुबह पिकअप चालक की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हो गई है और शव को भोपालगढ़ चिकित्सालय में रखवाया गया है। पुलिस के अनुसार रजलानी भोपालगढ़ निवासी रामकिशोर पुत्र झूमराम को किसी पिकअप के चालक ने पैदल जाते समय अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में रामकिशोर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर भोपालगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाष स. 0294-2421255, 2420013, Helpline no.0294-2426262,
Email:- ceoudr.lsg@rajasthan.gov.in electricalumc50@gmail.com Website :- https://udaipurmc.org/
क्रमांक :–ननिउ/ विद्युत/2026–27/562 दिनांक :– 10.10.26
ई-बोली आमन्त्रण सूचना संख्या – ई 11/2026-27
नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विद्युत शाखा से सम्बंधित विभिन्न विकास कार्य जिसकी कुल अनुमानित लागत राशि 78.01 लाख हेतु ई–प्रोक्यूरमेन्ट के माध्यम से ऑनलाईन निविदा दिनांक 20.10.26 समय सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
UBN No UNP2627GLOB00113 आयुक्त
राज.संवाद/सी/26/11832 नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल नवलगढ़, झुन्झुनू (राज.)
क्रमांक :न.पा.न./2026–27/4114 दिनांक : 12.10.2026
ई-निविदा सूचना 03/2026-27
नगरपालिका नवलगढ़ की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए सील बंद निविदाये आमंत्रित की जाती हैं। निविदा website www.sppp.raj.gov.in से download कर देखी/प्राप्त की जा सकती हैं। RTPP एक्ट की शर्ते मान्य होंगी एवं अन्य शर्ते कार्यालय समय में देखी जा सकती हैं।
जिसके Nib Code व UBN Number निम्न प्रकार हैं।

Sr. No.	NIB Code	UBN No.
1	DLB2627A8569	DLB2627GLOB21970

राज.संवाद/सी/26/11865 अध्यक्ष अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर
क्रमांक :– नपपु/विकास/2026/2857 दिनांक:– 06.10.2026
:: ई-निविदा सूचना ::
नगर परिषद पुष्कर की ओर से राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनो जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो (निविदा पात्रता पंजीकरण के नियमो के अनुसार मान्य) जो निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से सिविल निर्माण कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्यो की कुल लागत	51.68 लाख
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	06.10.2026 TO 16.10.2026 समय 6 बजे तक
निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	21.10.2026 समय प्रातः 11 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि	21.10.2026 समय सांय 4 बजे तक

विस्तृत विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर एवं नगर पालिका के निर्माण विभाग के कार्यालय में भी देखी जा सकती है।
Nib Code :-

S.No.	UBN No.
1	DLB2627SLOB21200

राज.संवाद/सी/26/11797 आयुक्त, नगर परिषद पुष्कर

कार्यालय नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर
क्रमांक :– नपपु/विकास/2026/2859 दिनांक:– 06.10.2026
:: ई-निविदा सूचना ::
नगर परिषद पुष्कर की ओर से राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनो जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो (निविदा पात्रता पंजीकरण के नियमो के अनुसार मान्य) जो निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से सिविल निर्माण कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्यो की कुल लागत	51.68 लाख
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	06.10.2026 TO 16.10.2026 समय 6 बजे तक
निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	21.10.2026 समय प्रातः 11 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि	21.10.2026 समय सांय 4 बजे तक

विस्तृत विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर एवं नगर पालिका के निर्माण विभाग के कार्यालय में भी देखी जा सकती है।
Nib Code :-

S.No.	UBN No.
1	DLB2627SLOB21206

राज.संवाद/सी/26/11799 आयुक्त, नगर परिषद पुष्कर

खुद को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बताकर कारोबारी से 24 लाख रुपए ठगे

पुलिस ने फरार शातिर अंतर्राज्यीय ठग दंपती को गिरफ्तार किया

- आरोपी देश के कई राज्यों में इसी तरह की ठगी के मामलों में लिप्त रहे हैं
- पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों और ठगी गई रकम की बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है
- आरापी दम्पती को यूपी के सीतापुर जेल से गिरफ्तार कर बीकानेर लाया गया

बीकानेर, (निसं)। व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने खुद को नाल एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बताकर बीकानेर के एक कारोबारी परिवार से पारिवारिक रिश्ते कायम करने और फिर 24 लाख रुपये की ठगी कर फरार होने वाले शातिर अंतर्राज्यीय ठग दंपती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी रोहित बाजपेयी (44) और उसकी पत्नी अन्नू बाजपेयी (44) निवासी मकरंद नगर, कन्नौज को यूपी की सीतापुर जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपी देश के कई राज्यों में इसी तरह की ठगी के मामलों में लिप्त रहे हैं।

एसएचओ देवेन्द्रसिंह राठौड़ ने बताया कि जेएनवीसी थाना क्षेत्र स्थित मरुधर कॉलोनी, जयपुर रोड निवासी नवीन कुमार चौहान ने मुकदमा दर्ज कराया था। परिवादी की जयपुर रोड पर जेबीएफ डेकोर नाम से दुकान है। दिसंबर, 24 में रोहित बाजपेयी ग्राहक बनकर दुकान पर आया और खुद को नाल एयरपोर्ट का एटीसी अधिकारी बताया। बड़ा खर्च और उदारता दिखाकर उसने स्टाफ और कारोबारी का भरोसा जीता। इसके बाद आरोपी ने करणी नगर में किराए का मकान लिया और कारोबारी परिवार को सामाजिक आयोजनों, रिसॉर्ट पार्टियों और पारिवारिक समारोहों में आमंत्रित कर घनिष्ठता बढ़ा ली। सहानुभूति और विश्वास हासिल करने के बाद आरोपियों ने कारोबारी की पत्नी को बहन बनाकर भावनात्मक जाल बिछाया।

पहले छोटे-मोटे लेनदेन कर समय पर ब्याज सहित पैसे लौटाकर पूरा विश्वास जमाया। इसके बाद 26 मार्च, 25 को संपत्ति खरीद की डील अटकने और 50 लाख का फर्जी बैंक स्टेटमेंट दिखाकर 20 लाख रुपये नकद और करीब 4 लाख रुपये के आभूषण ले लिए। रकम हाथ लगते ही 27 मार्च को आरोपी अपना मोबाइल बंद कर और किराए का मकान खाली कर रातों-रात फरार हो गए थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी सीतापुर (यूपी) कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में वहां की जेल में बंद हैं। जांच अधिकारी एएसआई जयप्रकाश मय जाब्ता सीतापुर कारागार पहुंचे और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दोनों को गिरफ्तार कर बीकानेर लाए हैं। पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों और ठगी गई रकम की बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है।

अजमेर में सूने मकान से पांच लाख का माल पार

- परिवार 18 दिन तक घर से बाहर था, लौटने पर चोरी की वारदात खुली, 50 हजार की नकदी, सोने-चांदी के आभूषण लेकर फरार हुए चोर

अजमेर, (निसं)। अजमेर में सूने मकानों को निशाना बनाने वाले चोरों के हौसले बुलंद हैं। कृष्णगंज थाना क्षेत्र के विकासपुरी, शांतिपुरा में चोरों ने एक बंद मकान में सेंध लगाकर नकदी और सोने-चांदी के आभूषण सहित करीब 5 लाख रुपये का माल चोरी कर लिया। परिवार के घर लौटने पर वारदात का पता चला। सूचना मिलने पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, विकासपुरी, शांतिपुरा निवासी शैलेंद्र कुमार धूत 25 सितंबर से 12 अक्टूबर तक अपने परिवार के साथ घर से बाहर गए हुए थे। 12 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे जब वे घर लौटे तो मकान में चोरी होने का पता चला। चोरों ने घर को निशाना बनाते हुए नकदी और कीमती आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। परिवादी के अनुसार, चोर मकान से 50 हजार रुपये नकद, सोने का हार, कानों की बालियां और सोने की दो कड़ियां ले गए। इसके अलावा चांदी की दो मूर्तियां, चांदी के चम्मच-कटोरी के पांच सेट और चांदी की दो पायल भी चोरी हो गईं। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है। वारदात की सूचना मिलने पर कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में सुराग जुटा कर चोरी की वारदात का खुलासा करने के प्रयास में जुटी है।

चलती बस से नीचे गिरने से युवक की मौत

जोधपुर, (कासं)। शहर के करवड़ थाना क्षेत्र में आईआईटी गेट नंबर-2 के पास चलती बस से नीचे गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बीकानेर निवासी कृष्णा पी. माधवानी के रूप में हुई है। इस संबंध में मृतक के पिता पुरुषोत्तम माधवानी की रिपोर्ट पर करवड़ थाना पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

करवड़ थाने के हैडकांस्टेबल बनवारीलाल ने बताया कि पुरुषोत्तम माधवानी अपने पुत्र कृष्णा के साथ रात एक निजी बस में बीकानेर से नाथद्वारा के लिए रवाना हुए थे। रात में करवड़ क्षेत्र में आईआईटी गेट नंबर-2 के पास कृष्णा बस में बने शौचालय की ओर गया था। शौचालय से लौटते समय बस का मुख्य गेट खुला होने के कारण वह चलती बस से नीचे गिर गया। हादसे में उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के पिता ने रिपोर्ट में बस चालक पर तेज गति और लापरवाही से बस चलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल करवड़ पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

गोदाम में घुसकर हमला, सामान में तोड़फोड़ की

सुजानगढ़, (निसं)। शहर के जमालपुरा रोड पर तगाला मस्जिद के पास स्थित एक गोदाम में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने और सामान में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जावेद पुत्र सलीम पडिहार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, घटना 14 अक्टूबर को सुबह करीब 11:30 बजे की है। परिवादी ने बताया कि वह अपने पिता सलीम, माता जरीना तथा अन्य परिजनों के साथ गोदाम में मौजूद था। इसी दौरान उसके काका नौसाद व सराज भी वहां काम के सिलसिले में आए हुए थे। तभी इरफान माल देखने के लिए आया हुआ था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि नदीम, मुख्तार, नौसाद और जावेद सहित कुछ लोग एकराय होकर लाठी-डंडों से लैस होकर गोदाम में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। परिवादी का आरोप है कि हमलावरों ने उसके और उसके पिता के साथ मारपीट की तथा गोदाम में रखे सामान को अस्त-व्यस्त कर नुकसान पहुंचाया।

अलवर में पति-पत्नी ने परिचित के साथ एक करोड़ की धोखाधड़ी की

- क्रेडिट कार्ड यूज लेने पर एक प्रतिशत मुनाफे का झांसा दिया, व्यवसाय के लिए पैसों की जरूरत बताई
- न्यायालय के निर्देश पर अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

अलवर, (निसं)। अलवर में परिचितों के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के बाद भुगतान बंद करने का मामला सामने आया है। कालाकुआं निवासी परिवादी ने आरोपी हेमंत गुप्ता और उसकी पत्नी श्वेता खंडेलवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का कोर्ट में परिवाद पेश किया है। अब अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

परिवाद के अनुसार, हेमंत ने व्यवसाय के लिए पैसों की जरूरत बताकर परिचितों के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए लिए थे। शुरुआत में वह समय पर भुगतान करता रहा, लेकिन जुलाई 2026 से भुगतान बंद कर दिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि क्रेडिट कार्ड से करीब 92.19 लाख रुपए इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा पत्नी के इलाज के नाम पर 10 लाख रुपए भी बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए गए। न्यायालय के निर्देश पर अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि हेमंत गुप्ता से उसकी पुरानी जान-पहचान थी। दोनों के बीच विश्वास के संबंध थे। वर्ष 2020 में हेमंत ने अपने व्यवसाय के लिए कुछ समय के लिए पैसों की जरूरत बताते हुए परिवादी और उसकी पत्नी के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मांगे थे। उसने कार्ड से खर्च की गई राशि समय पर चुकाने और इसके बदले 1 प्रतिशत लाभ देने की बात कही थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, शुरुआत में हेमंत क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान समय पर करता रहा। इससे उसका विश्वास बढ़ गया। बाद में हेमंत ने परिवादी से उसके दोस्तों, परिवार के सदस्यों और स्टाफ के लोगों के क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल के लिए दिलवाने को कहा। इसके बाद कई लोगों के क्रेडिट कार्ड उसे इस्तेमाल करने के लिए दिए गए। परिवाद में क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल की गई राशि का अलग-अलग विवरण दिया गया है। इसके अनुसार, परिवादी के 27 क्रेडिट कार्ड से करीब 33.03 लाख रुपए, उसकी पत्नी के चार कार्ड से करीब 3.85 लाख रुपए और दूसरे दोस्त के 13 कार्ड से करीब 33.65 लाख रुपए इस्तेमाल किए गए। इसी तरह एक दोस्त के छह क्रेडिट कार्ड से करीब 6.71 लाख रुपए और परिवार के सदस्यों व स्टाफ के लोगों के कार्ड से करीब 14.93 लाख रुपए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।

परिवाद में इन सभी कार्ड से इस्तेमाल की गई कुल राशि करीब 92.19 लाख रुपए बताई गई है। परिवादी ने आरोप लगाया कि हेमंत ने अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज कराने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत बताई थी। इस पर उसने ऑनलाइन माध्यम से हेमंत के बैंक खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल की गई राशि और बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए रुपयों को मिलाकर कुल 1.02 करोड़ रुपए से अधिक का लेन-देन हुआ।

परिवाद के अनुसार, जुलाई 2026 से हेमंत ने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान करना बंद कर दिया। इसके बाद परिवादी और उसके परिचितों को बैंकों की ओर से बकाया राशि चुकाने के लिए कहा जाने लगा। परिवादी ने दावा किया कि उसे बैंकों की बकाया न्यूनतम राशि के रूप में करीब 5 लाख रुपए भी जमा कराने पड़े। परिवादी का आरोप है कि जब उसने हेमंत से रकम वापस मांगी तो वह पहले टालमटोल करता रहा। बाद में उसने फोन उठाना बंद कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार, हेमंत के कई मोबाइल नंबर बंद आने लगे। उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर भी बंद मिला। परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि हेमंत अपने परिवार के साथ घर से फरार हो गया है। फिलहाल अरावली विहार थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है।

जोधपुर में फर्जी नंबर प्लेट लगी बस जब्त

जोधपुर, (कासं)। शहर की सड़कों पर दौड़ती सिटी बसें फर्जी तरीके से भी चल रही है। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सिटी बसों का संचालन भी हो रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम पुलिया पर एक सिटीबस का संचालन जुलाई माह से फर्जी तरीके हो रहा था। इसका खुलासा 10 अक्टूबर को उसके पकड़े जाने पर हुआ। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इस सिटीबस का परिचालन किया जा रहा था। घटना को लेकर देवनगर थाने में प्रकरण दर्ज हुआ है। अज्ञात शख्स के बारे में अब पुलिस जांच कर रही है।

देवनगर पुलिस के अनुसार सुजान चारण की तरफ से केस दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 14 जुलाई से 10 जुलाई के मध्य में प्रथम पुलिया देवनगर में एक सिटी बस का संचालन हो रहा था। इस सिटी बस की नंबर प्लेट फर्जी तरीके से यूज ली जा रही थी। इस पर पुलिस के सहयोग से सिटी बस को सीज करने की कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टया पुलिस ने सिटी बस पर लगी नंबर प्लेट को अवैध माना। प्रकरण में द्व जांच एएसआई जगराम की तरफ से जा रही है।

कार्यालय नगर परिषद्, ब्यावर
Tel.No. 1462-258665, 257509 Email Add: npbeawar@gmail.com
क्रमांक/रोशनी/2026–27/9173 दिनांक:–07.10.2026
ई-निविदा सूचना 01/2026-27
निम्नांकित रोशनी सम्बन्धी कार्य करवाया जाने हेतु EWSD श्रेणी 1 के पंजीकृत ठेकेदारों से E-Procurement पर दिनांक 21.10.2026 को प्रातः 11:00 बजे तक ई–निविदायें आमंत्रित है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि	प्रासेसिंग फीस	निविदा शुल्क
1	नगर परिषद ब्यावर क्षेत्र कें विभिन्न स्थानों पर मिनी हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य	30.24	60496	500	1000
2	नगर परिषद ब्यावर क्षेत्र कें विभिन्न स्थानों पर नई स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य	50.00	100000	500	1000
3	नगर परिषद ब्यावर क्षेत्र कें विभिन्न स्थानों पर पोलो पर रोप लाईट (तिरंगा लाईट) लगाने का कार्य	15.00	30000	500	1000
4	नगर परिषद ब्यावर क्षेत्र कें विभिन्न स्थानों पर लगी समस्थ स्ट्रीट लाईट का राख–रखाव कार्य	68.40	136800	1500	1000

ई–निविदा से संबंधित विस्तृत शर्ते ई–निविदा फार्म के साथ संलग्न है। यह फर्म E Procurement एवं WWW.Sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
जिसका NIB code DLB2627A8574 है एवं UBN नम्बर निम्नानुसार है:–
1. DLB2627 SLOB21975
2. DLB2627 SLOB21977
3. DLB2627 SLOB21979
4. DLB2627 SLOB21980

आयुक्त
राज.संवाद/सी/26/11914 नगर परिषद्, ब्यावर

निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई दी मंत्रियों ने

मुख्यमंत्री भजनलाल ने जीत का श्रेय सभी को देते हुए इसे साझा प्रयासों का परिणाम बताया

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निकाय चुनावों की तर्ज पर आगामी पंचायती राज चुनावों में भी प्रचंड जीत दर्ज करने के लिए बुधवार को मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि ग्रामीण लोगों का जीवन सम्मानजनक एवं सुविधाजनक बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी डबल इंजन की सरकार इसी सोच के साथ काम कर रही है। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब हमारे गांव विकसित होंगे, गांवों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनेगी। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायती राज चुनाव गांवों के भविष्य और विकास की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इन चुनावों में ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जाएं, जो गांव की वास्तविक समस्याओं को समझें और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हों। इसके लिए उन्होंने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर "ट्रिपल इंजन" सरकार बनाने का आव्हान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के विकास की योजनाएं गांव के लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनें और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी विचार को धरातल पर

■ पंचायती राज चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए भी रणनीति बनाई भाजपा ने

उतारने के लिए प्रदेश सरकार ने विकसित गांव, विकसित वार्ड अभियान चलाया। ग्राम सभाओं के माध्यम से चौपालों पर बैठकर किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और बुजुर्गों से उनकी जमीनी आवश्यकताओं के सुझाव लिए गए। उसके आधार पर ग्राम विकास संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रदेश के ग्रामीणों की आकांक्षाओं, सुझावों और सामूहिक संकल्प का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के प्रेरणादायी सेवाकाल को समर्पित सेवा संकल्प रथ प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। इन रथों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक पात्र परिवार को योजनाओं का लाभ मिले।

मंत्रिपरिषद की औपचारिक बैठक के बाद विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने हाल ही संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले ऐतिहासिक जनादेश के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इसके बाद सभी मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि निकाय चुनावों में भाजपा को मिली शानदार जीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सफल रणनीति और बेहतरीन फ्लोर मैनेजमेंट का परिणाम है। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विजय सभी के साझा प्रयासों का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में से 202 में भाजपा के बोर्ड बने हैं। 10 नगर निगमों में से 9 में भाजपा के महापौर निर्वाचित हुए हैं। वहीं 30 नगर परिषदों और 163 नगर पालिकाओं में भाजपा के निकाय प्रमुख चुने गए हैं। प्रदेश के 9 जिलों में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी।

एक लाख का इनामी मादक पदार्थ तस्कर कंवराराम बाड़मेर से गिरफ्तार

नवरात्र में घर आया था पूजा करने, नेपाल भागने की तैयारी में था आरोपी

जयपुर (कासं)। राजस्थान पुलिस के मादक पदार्थ विरोधी कार्यबल (एएनटीएफ) ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन विषकपिल' के तहत तीन साल से फरार चल रहे एक लाख रुपए के इनामी तस्कर कंवराराम को बाड़मेर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस की टॉप नार्कों-25 सूची में शामिल है और उसके खिलाफ हत्या, मादक पदार्थ तस्करी सहित 14

■ पिछले तीन साल से फरार था आरोपी, पुलिस से बचने के लिए घर में पाल रखे थे आठ कुत्ते

से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी नवरात्र में नागणेची माता की पूजा करने अपने घर आया था। पूजा के बाद वह नेपाल भागने की तैयारी में था, लेकिन इससे पहले ही एएनटीएफ टीम ने उसे पकड लिया।

एएनटीएफ महानिरीक्षक विकास कुमार के अनुसार एएनटीएफ को सूचना मिली थी कि कुख्यात तस्कर कंवराराम नवरात्र में पूजा-अर्चना करने के लिए अपने घर आने वाला है। इस सूचना के आधार पर टीम ने उसके निवास के आसपास गुप्त निगरानी शुरू की। जैसे ही आरोपी घर पर नागणेची माता की पूजा कर रहा था, टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने फरारी जारी रखने के लिए बैग तैयार कर रखा था और वह नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लंबे समय से ठिकाने बदलकर रह रहा था। पुलिस के अनुसार कंवराराम (35) निवासी बाडमेर है। उसने वर्ष 2009 में दसवीं तक पढाई करने के बाद छोड़ दी थी। इसके बाद पेट्रोल पंप पर सेल्समैन और फिर वाहन चालक के रूप में काम किया। वर्ष 2010 में उसके खिलाफ मारपीट और वर्ष 2013 में हत्या का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद वह गंभीर अपराधों में शामिल हो गया। जेल से छूटने के बाद उसने अवैध शराब के कारोबार और फिर मादक पदार्थों की तस्करी का रास्ता अपना लिया।पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैले अवैध तस्करी नेटवर्क से जुड़े 14 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड में कई प्रमुख मामले शामिल हैं। एएनटीएफ के अनुसार फरारी के दौरान आरोपी ने अपने घर के आसपास सुरक्षा और निगरानी का विशेष इंतजाम कर रखा था। उसने आठ पालतू कुत्ते पाल रखे थे। किसी बाहरी व्यक्ति या पुलिसकर्मी के घर के आसपास पहुंचने पर कुत्ते भौंकने लगते थे, जिससे आरोपी सतर्क हो जाता था और मौके से फरार हो जाता था। इस बार पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर निगरानी रखी और पूजा के दौरान दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया।



एएनटीएफ ने "ऑपरेशन विषकपिल" अभियान चलाकर शातिर मादक पदार्थ तस्कर कंवराराम को बाड़मेर से गिरफ्तार किया।

डीएनए करने वाले की गवाही नहीं कराई, गैंगरेप के बाद हत्या करने वालों की फांसी की सजा रद्द

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप कर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और इसमें अभियोजन पक्ष को अपराध की कडी से कड़ी जोडनी थी। जिसमें डीएनए रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले विशेषज्ञ को गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया। इसके साथ अदालत ने मामला लालसोट की ट्रायल कोर्ट को वापस भेजते हुए कहा है कि डीएनए रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ को गवाह के तौर पर बुलाया जाए और बचाव पक्ष को भी सुनवाई का मौका दिया जाए। अदालत ने निचली अदालत को कहा है कि वह मामले की सुनवाई पूरी कर तीन माह में नए सिरे से फैसला करे। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस को खारिज कर आरोपियों की अपीलों को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश

■ अदालत ने मामला लालसोट की ट्रायल कोर्ट को वापस भेजते हुए कहा है कि डीएनए रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ को गवाह के तौर पर बुलाया जाए और बचाव पक्ष को भी सुनवाई का मौका दिया जाए।

में कहा कि ट्रायल कोर्ट के डीएनए रिपोर्ट पर निर्भर रहते हुए विशेषज्ञों के बयान नहीं लिए जाने से विचारण दूषित हो गया है।

डेथ रेफरेंस में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार पूनिया ने अदालत को बताया कि कालूराम और संजू ने 23 अप्रैल, 2022 को महिला का अपहरण कर उसके साथ कार में गैंगरेप किया था और बाद में उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। मामले में कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। ऐसे में एडीजे कोर्ट, लालसोट ने गत 19 फरवरी को दोनों अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 20 फरवरी को उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। राज्य सरकार की ओर से डेथ रेफरेंस पेश कर गुहार की गई की निचली अदालत के फैसले को कंफर्म किया जाए।

वहीं आरोपियों की ओर से कहा गया कि निचली अदालत ने मामले में डीएनए रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ के बयान ही नहीं लिए हैं। शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. चैन सिंह ने पेश होकर माना है कि उन्हें यह रिपोर्ट तैयार होने या एफएसएल परीक्षण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि जब सजा डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दी गई है तो इसे तैयार करने वाले विशेषज्ञ के बयान जरूरी थे।

अदालत की ओर से मामले में नियुक्त न्यायमित्र अधिवक्ता मोहित बलवदा ने भी इसे जरूरी बताया। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फांसी की सजा के आदेश को रद्द कर निचली अदालत को डीएनए करने वाले विशेषज्ञ के बयान दर्ज कर नए सिरे से मामले में फैसला करने को कहा है।

श्री गोपीनाथजी मंदिर में लगेगा छप्पन भोग

जयपुर। श्री गोपीनाथजी मंदिर में आचार्य लवभूषण के जन्मदिवस के अवसर पर 15 अक्टूबर (गुरुवार) को छप्पन भोग महोत्सव आयोजित किया जाएगा।

मंदिर परिसर में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होने वाले इस आयोजन में भगवान श्री गोपीनाथजी को छप्पन भोग अर्पित कर पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। आयोजन को लेकर कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अमृता हाट में खरीददारी की

महिला स्वयं सहायता समूहों का उत्साह बढ़ाया

जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं महिला-बाल विकास मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार शाम जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय अमृता हाट का अवलोकन किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं के स्टॉल पर पहुंचकर उनके उत्पादों की सराहना की, उनका उत्साहवर्धन किया और खरीददारी भी की।

दीया कुमारी ने महिलाओं को बिक्री बढाने के लिए केवल प्रदर्शनियों पर निर्भर नहीं रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल विपणन और ऑनलाइन मंचों के माध्यम से महिलाएं अपने उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचा सकती हैं। इससे उन्हें अधिक ग्राहकों तक पहुंचने और अपने कारोबार का विस्तार करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अमृता हाट में भाग ले रही महिलाओं के लिए मेले के दौरान ही डिजिटल विपणन का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमी बने और उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। उल्लेखनीय है कि जवाहर कला केंद्र में 11 से 20 अक्टूबर तक आयोजित इस राज्य स्तरीय अमृता हाट में 170 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण और अन्य स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जा रहा है।



उपमुख्यमंत्री एवं महिला-बाल विकास मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार शाम जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय अमृता हाट का अवलोकन किया।

मानक ही समाज, उत्पाद और विचार को श्रेष्ठ बनाते हैं : हरिभाऊ बागड़े

जयपुर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि श्रेष्ठता केवल भौतिक पैमानों से नहीं, बल्कि वैचारिक, नैतिक और व्यावहारिक शुद्धता से भी तय होती है। मानक ही किसी समाज, उत्पाद या विचार को सामान्य से श्रेष्ठ बनाते हैं। उन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो से गुणवत्ता, मानकीकरण, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढाने का आ ान किया।

राज्यपाल बुधवार को कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से आयोजित विश्व मानक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में श्रेष्ठता जीवन का आधार रही है। आईएसआई मार्क और हॉलमार्क जैसे मानक विश्वास के प्रतीक हैं। मानकों के पालन से जीवन सुरक्षित और सुगम बनता है तथा भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ती है। राज्यपाल ने उत्पादों, सेवाओं और तकनीकी क्षेत्रों के मानक निर्धारित करने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं विशेषज्ञों के योगदान की सराहना की।

महापौर-उपमहापौर ने किया स्वच्छता सेवा में श्रमदान

जयपुर। नगर निगम की ओर से शहर में स्वच्छता ही सेवा-2026 एवं विकसित भारत जन सेवा अभियान के अंतर्गत वार्ड वार विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को नगर निगम महापौर सुनील कोठारी ने वार्ड-135 में पहुंच कर विशेष स्वचछता अभियान का निरीक्षण किया और कमियां सुधारने को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान उन्होंने पार्षद विमल अग्रवाल, जोन उपायुक्त, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक सतपाल टोपिया, जितेंद्र, स्वास्थ्य निरीक्षक सुरेन्द्र , सुनील गुर्जर, जोन एक्सईएन, जोन जेईएन, नगर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजन से संवाद किया। महापौर ने नागरिकों को कचरा निर्धारित समय पर निगम की कचरा संग्रहण गाडिय़ों में डालने तथा सड़क पर कचरा ना फैलाने के लिए जागरूक किया।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं सुंदर जयपुर के निर्माण में नगर निगम के साथ जनभागीदारी भी आवश्यक है। इस अवसर पर महापौर ने भी स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। पार्षद, जोन उपायुक्त, निगम अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भी

■ दोनों ने सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण भी किया

सफाई कार्य में सहयोग किया।

महापौर द्वारा वार्ड 16 में चौमूं पुलिया पर अभियान का औचक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान वार्ड के ब्लॉक अनुसार कर्मचारियों का आवंटन एवं समस्त शाखाओं से वार्ता एवं सफाई व्यवस्था के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए। वार्ड नम्बर 33 में आयोजित स्वच्छता उत्सव में उपमहापौर सरोज कंवर भी पहुंची। उप महापौर की उपस्थिति में वार्ड पार्षद सीमा महेंद्र यादव, वार्ड समिति अध्यक्ष, विद्युत विभाग, गार्डन शाखा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक एवं टीम को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सफाई कर्मियों द्वारा चिन्हित स्थानों पर स्वच्छता श्रमदान किया गया तथा विशेष सफाई अभियान चलाकर वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में साफ-सफाई की गई। साथ ही स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर एवं प्रभावी बनाने के लिए उपमहापौर ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

"शब्द शक्ति-संगम" में गूंजा नारी शक्ति का वैचारिक जयघोष

जयपुर। "शब्द रसायन" संस्थान की ओर से बुधवार को रामबाग स्थित एस. एस. जैन सुबोध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में "शब्द शक्ति-संगम" आयोजित किया गया। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी एवं भारतीय कोच सुरभि मिश्रा, भारत की पहली महिला आईएनएस विक्रमादित्य कमांडर प्रियंका चौधरी तथा प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं स्तंभकार प्रो. ऋतु सारस्वत ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद किया।

संस्थान के निदेशक डॉ. रेवंत दान और मानद सचिव मुरारी गुप्ता ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा और वैचारिक संस्कारों से जोड़ना था। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. रेणु जोशी ने स्वागत भाषण दिया। डॉ. रेवंत दान ने विषय की प्रस्तावना रखी, जबकि मुरारी गुप्ता ने 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता की जानकारी दी। सुरभि मिश्रा ने अस्थमा की समस्या के बावजूद स्क्वैश में करियर बनाने के अपने संघर्ष को साझा करते हुए युवाओं को अपनी प्रतिभा पहचानने का संदेश दिया। प्रियंका चौधरी ने नौसेना में अपने अनुभवों और साहसिक अभियानों में भागीदारी के बारे में बताया।

गहलोत स्पष्ट करें, पायलट के साथ हैं या आज भी पुराने बयान पर कायम हैं : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार करते हुए परिसीमन, महिला आरक्षण और कांग्रेस की आंतरिक राजनीति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गहलोत पहले स्पष्ट करें कि वे सचिन पायलट के साथ हैं या आज भी उन्हें पहले की तरह नाकारा और निकम्मा मानते है। राठौड़ ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि, "गहलोत साहब की कुर्सी की चाह, छटपटाहट और खीझ उनके बयानों से स्पष्ट होती है। परिसीमन के नाम पर अर्नगल बयानबाजी करने वाले अशोक गहलोत खुद यह भूल रहे हैं कि, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए नगर निकायों का परिसीमन इस तरह करवा चुके हैं कि भाजपा को राजनीतिक नुकसान हो। उन्होंने कहा कि अब परिसीमन का मुद्दा उठाकर कांग्रेस अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। उनके अनुसार, कांग्रेस कई राज्यों में दशकों से सत्ता से बाहर है, इसलिए उसे अपनी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।"महिला आरक्षण के मुद्दे पर राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिलाओं को अधिकार देने की प्रक्रिया में बाधाएं खड़ी कीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्रस्ताव का भी उल्लेख किया, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की बात कही गई थी। राठौड़ ने कांग्रेस और चीन के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि देश को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर जनादेश और संविधान की व्यवस्थाओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। राठौड ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायपालिका की अपनी व्यवस्थाएं एवं मर्यादाएं हैं, जिनका पालन सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए।

प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए डीजीपी ने कसी पुलिस की लगाम

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत रखने और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय में बुधवार को अपराध एवं कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक आयोजित की गई। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े पुलिस अधिकारियों को पूर्ण सतर्कता बरतने और प्रत्येक परिस्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में लंबित प्रकरणों के निस्तारण, संवेदनशील घटनाओं की निगरानी,

■ अपराध नियंत्रण से लेकर चुनाव सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा कर निर्देश दिए

अपराध नियंत्रण, आगामी पंचायती राज चुनावों और पर्व-त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। बैठक में सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस जिलों के पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विवादित मामलों की होगी नियमित समीक्षा

डीजीपी शर्मा ने कहा कि जिन विवादित मामलों से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है, उन्हें प्राथमिकता से चिह्नित किया जाए। ऐसे मामलों की सूची तैयार कर थाना, वृत्त और जिला स्तर पर



महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा

नियमित निगरानी की जाए। राजस्व, वन विभाग सहित संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जाए। विवादों को गंभीर रूप लेने से रोकने के लिए समझाइश, निरोधात्मक कार्रवाई और अन्य वैधानिक उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए।

पुलिसकर्मियों के आचरण पर भी नजर

बैठक में पुलिसकर्मियों की अपराधों में संलिप्तता के मामलों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे कार्मिकों की पहचान, निगरानी और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

डीजीपी ने कहा कि पुलिस थानों और फील्ड में तैनात कार्मिकों का व्यवहार आमजन के प्रति संवेदनशील, सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक होना चाहिए। परिवादियों की नियमित सुनवाई कर उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

संवेदनशील घटनाओं में त्वरित कार्रवाई

डीजीपी ने हाल में हुई विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए संवेदनशील और गंभीर मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावी पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए। घटनाओं की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने, तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करने और प्रेस तथा सोशल मीडिया के माध्यम से समय पर तथ्यपरक जानकारी साझा करने पर जोर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुराने मामलों के निस्तारण की जवाबदेही

पुलिस थानों में लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के लिए डीजीपी ने स्पष्ट जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा संबंधित पुलिस अधीक्षक करेंगे, जबकि तीन वर्ष से अधिक अवधि से लंबित मामलों की समीक्षा रेंज आईजी करेंगे।

पुराने मुकदमों के साथ लंबित चालान और अंतिम रिपोर्ट (एफआर) के निस्तारण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने तथा मामलों में आ रही बाधाओं को दूर करने पर भी जोर दिया गया।

अपराध बढ़ने वाले जिलों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश

डीजीपी ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय दंड संहिता (भादंसं) के तहत दर्ज प्रकरणों में पांच प्रतिशत से अधिक वृद्धि वाले जिलों को अपराधों का विश्लेषण कर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। महिला अत्याचार के मामलों में अधिक वृद्धि वाले जिलों को कारणों की समीक्षा कर ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत अपेक्षाकृत कम प्रकरण दर्ज करने वाले जिलों को मादक पदार्थों के विरुद्ध सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत कम कार्रवाई करने वाले जिलों की भी समीक्षा कर अपेक्षित सुधार सुनिश्चित करने को कहा गया।

पंचायती राज चुनाव और त्योहारों पर पुख्ता सुरक्षा

आगामी पंचायती राज चुनावों और पर्व-त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी जिलों को आवश्यक पुलिस बल की तैनाती की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता, असामाजिक तत्वों की पहचान, निरोधात्मक कार्रवाई, नियमित गश्त और प्रभावी नाकाबंदी सुनिश्चित करने को कहा गया। डीजीपी ने कालिका पेट्रोलिंग इकाइयों की फील्ड में सक्रिय उपस्थिति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।

नाकाबंदी में बॉडी कैमरे, यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती

डीजीपी ने नाकाबंदी के दौरान पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरों का उपयोग करने के निर्देश दिए। शराब पीकर वाहन चलाने, संदिग्ध वाहनों और तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस का प्रतिक्रिया समय न्यूनतम रखने और घटनास्थल पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

साइबर अपराधों में जीरो एफआईआर पर जोर

अपराधों की रोकथाम के लिए निरोधात्मक और सक्रिय पुलिसिंग मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इसके तहत राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज (राजपासा), बीएनएस की संबंधित धाराओं, गुंडा एक्ट और एनडीपीएस से जुड़े निरोधात्मक प्रावधानों सहित अन्य वैधानिक उपायों का प्रभावी उपयोग करने को कहा गया। साइबर अपराधों के मामलों में जीरो एफआईआर दर्ज कर अधिकाधिक पीड़ितों को राहत पहुंचाने और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

राजस्थान की आर्द्रभूमियों की पहचान और संरक्षण करे सरकार : एनजीटी

भोपाल/जयपुर (कासं)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल ने राजस्थान सरकार को राज्य की आर्द्रभूमियों की पहचान, सीमांकन, अधिसूचना और संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई कर चार सप्ताह में कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर 2026 को होगी। यह आदेश मूल आवेदन संख्या 225/2026 (सीजेड) में 9 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति श्योकुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने पारित किया। अधिकरण ने आनंद आर्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर 2024 के आदेश का भी उल्लेख किया।एनजीटी ने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एसएसी) के वर्ष 2021 के एटलस में चिह्नित आर्द्रभूमियों का स्थलीय सत्यापन कर उनकी सीमाएं निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी आर्द्रभूमियों के बफर जोन और प्रभाव क्षेत्र को अंतिम रूप देने तथा अब तक अधिसूचित नहीं हुई आर्द्रभूमियों की पहचान, सीमांकन और अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

सार-समाचार

डी.सी.एम. श्रीराम लिमिटेड में रामलीला का मंचन

कोटा, (निसं)। डी.सी.एम. श्रीराम लिमिटेड द्वारा 2 दिवसीय रामलीला का मंचन 19 अक्टूबर एवं 20 अक्टूबर को श्रीराम कला मंदिर में किया जायेगा। रामलीला का समय 19 अक्टूबर को सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक होगा। दशमी के दिन 20 अक्टूबर को कार्यक्रम सायं 6:15 बजे शुरू होगा। इस रामलीला में काम करने वाले कलाकार डी.सी.एम. श्रीराम लिमिटेड़, कोटा स्थित कारखाने में कार्यरत कर्मचारी व उनके परिवारजन हैं। इन कलाकारों की संख्या लगभग 80 है। इन सभी कलाकारों के लिये आकर्षक वेशभूषा की व्यवस्था की गई है। इस बार के विशेष आकर्षणों में भावविभोर करने वाले नृत्य, गणेश वंदना, रामलीला मंचन के दौरान गाई जाने वाली चौपाईयों की सुंदर व शुद्ध रूप में प्रस्तुति, हनुमान चालीसा एवं छाया दृष्टि आदि प्रमुख हैं। दिनाँक 19 अक्टूबर को हनुमान जी का आकाश मार्ग से आना एवं कुंभकरण-मेघनाद वध भी दर्शकों, खासकर बच्चों के लिये कौतूहल का विषय होगा। 20 अक्टूबर को होने वाले रावण दहन में रावण के पुतले की लम्बाई 72 फीट, कुम्भकरण तथा मेघनाद की 50 फीट होगी। विजय दशमी के दिन रावण दहन के पश्चात राज दरबार के मनोहारी दृश्य में राजतिलक का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जायेगा। इस वर्ष रामलीला के सजीव एवं बेहतर मंचन हेतु प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न सेट्स का चित्रण भी किया जाएगा। कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने व सुरक्षा की दृष्टि से कम्पनी के सिक्यूरिटी के कर्मचारी तथा अन्य अधिकारी जगह-जगह पर तैनात रहेंगे।

हरित ऊर्जा की ओर बढ़ता कोटा मंडल, सौर ऊर्जा क्षमता 4.542 मेगावाट पहुंची

कोटा, (निसं)। पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और पारंपरिक विद्युत पर निर्भरता कम करने की दिशा में पश्चिम मध्य रेलवे का कोटा मंडल सौर ऊर्जा के उपयोग का लगातार विस्तार कर रहा है। मंडल में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता अब 4.542 मेगावाट हो गई है। इन संयंत्रों से प्रतिवर्ष औसतन 66.31 लाख यूनिट हरित विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जिससे रेलवे को सालाना लगभग 2.60 करोड़ की बचत हो रही है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोटा मंडल में कुल 1054 किलोवाट (1.054 मेगावाट) क्षमता के नए रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए। इनमें उपलब्ध विवरण के अनुसार गंगापुर सिटी में 222 किलोवाट, सवाई माधोपुर में 300 किलोवाट, तुगलकाबाद में 400 किलोवाट तथा भरतपुर में 80 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र शामिल हैं। हरित ऊर्जा के इस नेटवर्क को आगे और मजबूत करने के लिए मंडल में 2340 किलोवाट (2.340 मेगावाट) अतिरिक्त सौर क्षमता स्थापित करने की योजना है। इन परियोजनाओं के लिए संबंधित एजेंसियों को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी किए जा चुके हैं तथा आगे की कार्यवाही प्रगति पर है। सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से बिजली व्यय में कमी के साथ पर्यावरण अनुकूल रेल संचालन को भी बढ़ावा मिल रहा है।

बाल मेले का आयोजन

रामगंजमंडी, (निसं)। पीएम श्री श्री हीरा भाई परीख रा.बा.उ. मा. वि. रामगंजमण्डी में 14 अक्टूबर बुधवार को ईसीसीई दिवस एवं बाल मेला समारोह हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ विद्यालय की प्रधानाचार्य गार्गी मेहता, उपप्राचार्य बीना सोनी एवं एस एम सी सदस्यों द्वारा माँ सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात् बालिकाओं द्वारा स्वागीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया गया। विद्यालय परिवार की ओर से अतिथियों एवं अभिभावकों का आत्मीय अभिनंदन किया गया। बाल मेले में विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए मिट्टी के खिलौने, रचनात्मक कलाकृतियाँ एवं आकर्षक पोस्टरों की प्रदर्शनी लगाई गई। विद्यालय के समस्त स्टॉफ, अतिथियों एवं अभिभावकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा बच्चों की रचनात्मकता और कलात्मक प्रतिभा की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान बालवाटिका के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जलेबी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं अभिभावकों के लिए नींबू दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई।

1500 से अधिक संभागियों ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया

कोटा, (निसं)। भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र, शाखा कोटा की ओर से केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-1, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीपुरा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरजपोल में नशा मुक्ति जागरूकता एवं सिद्ध योग ध्यान शिविर आयोजित किए गए। तीनों विद्यालयों में कुल 1440 विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं स्टाफ ने भाग लेकर नशामुक्त रहने का संकल्प लिया। शिविरों में 15 मिनट का ध्यान करवाया गया। एवीएसके जोधपुर के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख रामलाल मालव ने बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा एवीएसके जोधपुर के बीच गत माह नई दिल्ली में हुए एमओयू के तहत यह आयोजन किया गया। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर स्वस्थ, सकारात्मक एवं नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करना है।

कोटा-चौमहला मेमू 17 से 20 अक्टूबर तक शामगढ़ तक ही चलेगी

कोटा, (निसं)। कोटा-नागदा रेलखंड में सुवासरा-नाथूखेड़ी स्टेशनों के बीच समपार फाटक संख्या 40 पर निर्माणाधीन रोड ओवरब्रिज (आरओबी) के स्टील गर्डर लगाने के कार्य के कारण 17 से 20 अक्टूबर तक कोटा-चौमहला-कोटा मेमू ट्रेन का संचालन शामगढ़ स्टेशन तक सीमित रहेगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि 17 से 20 अक्टूबर तक गाड़ी संख्या 61616 कोटा-चौमहला मेमू शामगढ़ स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 61615 चौमहला-कोटा मेमू चौमहला के स्थान पर शामगढ़ स्टेशन से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी। इस प्रकार दोनों दिशाओं में यह ट्रेन शामगढ़-चौमहला के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी, ट्रेन की जानकारी के लिए एनटीईएस अथवा रेल मदद 139 का उपयोग करें।

पंचायती राज चुनाव में मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा

कोटा, (निसं)। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव प्रथम चरण में 23 अक्टूबर, पंच एवं सरपंच पदों के चुनाव प्रथम चरण में 25 अक्टूबर तथा द्वितीय चरण पंचायत समिति खैराबाद व चेचट में 29 और 31 अक्टूबर को मतदान दिवस पर संस्थानों में कार्यरत कामगारों के लिए अवकाश रहेगा। संयुक्त श्रम आयुक्त दीपक यादव ने बताया कि मतदान के दिवसों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को अपने संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों, जिनमें आकस्मिक श्रमिक भी शामिल हैं, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान करना होगा, ताकि श्रमिकों को अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग करने का अवसर मिल सके।

जल प्रवाह जल्द प्रारंभ किया जायेगा

मांगरोल, (निसं)। गणेशगंज लिफ्ट नहर में जल प्रवाह के संबंध में जल संसाधान सहायक अभियंता उपखण्ड मांगरोल के ने बताया की मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत गणेशगंज लिफ्ट की मोटर बदल कर नये मोटर पम्प स्थापित किये जाने का कार्य प्रगतिरत हैं इस कार्य के तहत सभी पुराने मोटर पम्पो को बदल कर उनके स्थान पर 150 एचपी के 6 नये मोटर पम्प स्थापित किये जाने हैं संवेदक द्वारा नये मोटर पम्प हेतु किर्लोस्कर कम्पनी को ऑर्डर दिया जा चुका हैं नये मोटर पम्पो की डिलीवरी अक्टूबर माह के अन्त तक मिलने की संम्भावना हैं ऐसे में किसानों को समय पर पानी उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा पम्प हाउस का जीर्णोद्वार करवाया जाकर नहरों की साफ सफाई का कार्य करवाया जा रहा हैं एवं किसानों को समय पर सिंचाई जल उपलब्ध करवाने हेतु पुराने मोटर पम्पो को स्थापित करवाया जा रहा है।

'चम्बल घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के प्रकरणों में सख्त कार्रवाई करें'

कोटा, (निसं)। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण आनंद कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कोटा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं संकटग्रस्त जलीय जीवों के लिए खतरे से संबंधित प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में कोटा-बूंदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन की प्रभावी रोकथाम के लिए अभी तक उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुए अवैध बजरी खनन रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने एवं सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि अवैध खनन वाले संवेदनशील वाले स्थानों को चिन्हित करें एवं वहां लगातार पेट्रोलिंग की जाए। अवैध बजरी परिवहन करने वाले वाहनों के मार्गों को चिन्हित कर मोबाइल चौकी स्थापित करें एवं लगातार चौकिंग कर कार्रवाई करें। उन्होंने घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन के मामलों में पिछले वर्ष की गई कार्रवाई, वन विभाग, खान विभाग एवं पुलिस की ज्वॉइंट पेट्रोलिंग, जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठकों आदि के बारे में जानकारी ली। अवैध बजरी खनन के खिलाफ की गई सभी कार्रवाईयों की विभागवार समीक्षा करते हुए उन्होंने कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन, पुलिस, खनन विभाग एवं वन विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत समीक्षा कर निर्देश दिए कि अवैध बजरी खनन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को जब्त करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर मोबाईल चेक पोस्ट की स्थापना की जाए। वन विभाग, पुलिस एवं खान विभाग द्वारा समन्वय स्थापित कर नियमित रूप से इन सभी क्षेत्रों में आवश्यक रूप से पेट्रोलिंग की जाए। सभी संबंधित विभाग संयुक्त रूप से गश्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने, अवैध खनन वाले गांवों में मुखबिर तैयार करने तथा सभी संबंधित विभागों के आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।

आईजी कोटा रेंज हरेन्द्र महावर ने बताया कि सीसीएफ कोटा एवं सीसीएफ वाईल्ड लाईफ कोटा के साथ 13 अक्टूबर को घघटाना, कोटसुंवा एवं मानस गांव में निरीक्षण किया गया था। डीसीएफ रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व

■ **संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लगातार पेट्रोलिंग की जाए : अतिरिक्त मुख्य सचिव**

अरुण कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि 10 अक्टूबर को फील्ड डायरेक्टर, आरवीटीआर के निर्देशन में डोलार, रोडगंज एवं नोताड़ा में फील्ड विजिट किया गया। उन्होंने बताया कि संवेदनशील चेक पोस्ट पर बोर्डर होमगार्ड लगाए गए हैं। अवैध खनन पर निगरानी के लिए होमगार्ड को वेपन एवं बॉडी कैम दिए गए हैं। साथ ही, 14 वॉयरलेस सेट, एक थर्मल ड्रोन एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि बूंदी के केशोरायपाटन, लाखेरी एवं इंदरगढ़ थाने के प्रभारी एवं पुलिस कर्मियों को साथ लेकर वन एवं खान विभाग के अधिकारियों द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की जा रही है।

डीसीएफ रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व ने बताया कि बूंदी जिले में 1 अप्रेल से अभी तक अवैध बजरी खनन के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए आरवीटीआर क्षेत्र में अवैध खनन के 12 प्रकरण वन विभाग द्वारा दर्ज करते हुए अवैध बजरी परिवहन कर रहे 7 वाहन जब्त किए गए। परिवहन विभाग द्वारा 148 मामलों में कार्रवाई करते हुए 28 वाहन जब्त किए गए। पुलिस एवं खान विभाग द्वारा 25 मामलों में कार्रवाई करते हुए 44 वाहन जब्त किए गए। इसी प्रकार कोटा जिले में आरवीटीआर क्षेत्र में वन विभाग द्वारा 20 प्रकरण दर्ज करते हुए 18 वाहन जब्त किए गए। पुलिस विभाग द्वारा कोटा में 11 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 9 वाहन जब्त किए गए एवं 4 को गिरफ्तार किया गया। माइंस विभाग द्वारा 8 प्रकरणों में कार्रवाई की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि भारी वाहनों, जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों आदि में आवश्यक रूप से जीपीएस सिस्टम लगा होना चाहिए। साथ ही, जीपीएस सिस्टम की नियमित रूप से सघन मॉनिटरिंग की जाए, ताकि घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र में अवैध खनन में प्रयुक्त होने वाले सभी वाहनों की जानकारी मिल सकें। उन्होंने जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिए कि बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल पम्प से ईंधन उपलब्ध नहीं हो, इसकी सख्त मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पम्प पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों की फीड चेक कर इस तरह के वाहनों की सूची बनाकर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक बजरी के प्रभावी विकल्प के रूप में एम-सेण्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आमजन में जागरूकता बढ़ाई जाए। अवैध खनन व इसके परिवहन की प्रभावी रोकथाम के लिए जमीनी स्तर पर निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाऐं।

खान विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि कोटा जिले में एम-सेण्ड की 9 यूनिट जबकि बूंदी जिले में 4 यूनिट संचालित हैं। कोटा जिले में 3 और यूनिट दिसंबर माह तक शुरू हो जाएंगी जिससे एम-सेण्ड की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी एवं मकान निर्माण में बजरी पर निर्भरता कम होगी।

बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरुण प्रसाद, संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर कोटा पीयूष समारिया, सीसीएफ वाइल्ड लाइफ कोटा टी. मोहनराज, जिला कलेक्टर बूंदी हरफूल सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक कोटा शहर तेजस्वनी गौतम, कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर, बूंदी एसपी अवनीश कुमार शर्मा, डीसीएफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व मुथु एस., डीसीएफ कोटा यादवेन्द्र सिंह, एडीएम प्रशासन राजेश जोशी सहित खान, परिवहन, पुलिस एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

गरबा महोत्सव का रंगारंग आयोजन

कोटा, (निसं)। लायंस क्लब कोटा साउथ द्वारा बसंत विहार स्थित क्लब भवन में गरबा महोत्सव का रंगारंग आयोजन अत्यंत उल्लास व उमंग के साथ किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्लब के सम्मानित सदस्यों एवं उनके परिवारजनों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा की सामूहिक आरती और वंदना के साथ हुआ। आरती के उपरांत सदस्यों ने मां का आशीर्वाद प्राप्त किया और मनमोहक गरबा की प्रस्तुतियां दीं। सभी महिला एवं पुरुष सदस्य पारंपरिक, रंग-बिरंगे और आकर्षक परिधानों में सज-धजकर पहुंचे थे। महिलाओं, पुरुषों और कपल्स के लिए आयोजित अलग-अलग गरबा एवं डांडिया राउंड्स ने समारोह में समां बांध दिया। मधुर संगीत की धुनों और डांडिया की खनक से पूरा क्लब भवन उत्सव के आनंद से सराबोर हो उठा। उपस्थित सदस्यों ने एक-दूसरे के साथ गरबा-डांडिया का भरपूर आनंद लेते हुए आपसी प्रेम, सौहार्द और पारिवारिक एकता की मिसाल पेश की। सांस्कृतिक उल्लास के साथ-साथ क्लब ने अपने सामाजिक सरोकारों को भी पूरी प्रमुखता दी। आयोजन के दौरान चाईल्डहुड कैंसर अवेयरनेस (बाल कैंसर जागरूकता) से जुड़े पर्चे वितरित किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना था, ताकि वे अपने परिवार, पड़ोस और समाज में लोगों को इसके लक्षण और समय पर इलाज के प्रति सचेत कर सकें।

मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन के लिए विशेष शिविर

कोटा, (निसं)। रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा और सहायता की जिम्मेदारी निभाने वाले आरपीएफ कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन के लिए आरपीएफ रिजर्व लाइन में हार्टफुलनेस के सहयोग से विशेष शिविर आयोजित किया गया, शिविर में 51 आरपीएफ कर्मियों ने भाग लिया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्री सुरक्षा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में आरपीएफ कर्मियों के लिए मानसिक सतर्कता, धैर्य और एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नियमित ध्यान एवं योग का अभ्यास तनाव कम करने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। शिविर में हार्टफुलनेस के पुष्पेंद्र शर्मा ने कर्मचारियों को ध्यान एवं योग का अभ्यास कराते हुए तनाव प्रबंधन के सरल तरीके बताए, इस अवसर पर आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त यशवंत सिंह उपस्थित रहे।

विसर्जित गणेश प्रतिमा की पवित्र मिट्टी को 121 गमलों में भरकर जेड प्लांट युक्त गमले सौंपे

कोटा, (निसं)। पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक परंपराओं का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करते हुए सर्व हिंदू समाज सोशल क्रांतिकारी महासंघ इको फ्रेंडली श्री गणपति क्लबश के मुख्य संयोजक गोविंद नारायण अग्रवाल अध्यक्ष डॉ.एम.एल. अग्रवाल के संयोजन में गणेश महोत्सव के अवसर पर एक अनुकरणीय नवाचार किया है। क्लब द्वारा आस्था और प्रकृति के संतुलन का संदेश देते हुए गणेश विसर्जन के पश्चात प्राप्त पावन रज का सदुपयोग कर पर्यावरण संवर्धन के लिए उपयोग में लिया गया है।

अध्यक्ष गोविंदनारायण अग्रवाल ने बताया कि गणेश उत्सव के दौरान राधा कृष्ण मंदिर समिति, तलवंडी में इको फ्रेंडली श्री गणपति क्लब के द्वारा निःशुल्क ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा उपलब्ध कराई गई थी। मंदिर समिति द्वारा 10 दिनों तक विधिवत पूजा-अर्चना के बाद प्रतिमा को मंदिर परिसर में ही स्थापित जलकुंड में विसर्जित किया गया। जिन लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं को स्थापित करते हुए विसर्जन किया उन्हें जल कुंड से बाहर निकाल कर विशेष गमले तैयार किए गए। जिसमें मिट्टी से निर्मित प्रतिमाओं के विसर्जन के पश्चात बची पावन रज मिट्टी को गमले में भरकर पौधे रोपित किए गए। जो धार्मिक आस्था और पर्यावरण सुरक्षा का सशक्त उदाहरण बने।

121 रजिस्टर्ड सदस्यों को बांटे गए जेड प्लांट:- नवरात्रा चतुर्थी के शुभ अवसर पर पूर्व पंजीकृत 121 परिवारों को ये विशेष गमले नि:शुल्क वितरित किए गए। वितरण समारोह में सभापति राकेश अग्रवाल, अध्यक्ष गोविंद नारायण अग्रवाल और महामंत्री जितेंद्र गोयल द्वारा सदस्यों को जेड प्लांट युक्त गमले सौंपे गए। अध्यक्ष गोविंद नारायण अग्रवाल ने बताया कि विसर्जन की रज से महके हर घर सोच के साथ इस अनुष्ठान को केवल धार्मिक आस्था तक सीमित न रखकर पर्यावरण संवर्धन से जोड़ा गया है। गमलों में लगाए गए जेड प्लांट वास्तु एवं सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं, जो आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के साथ-साथ मानसिक तनाव को दूर करने में भी सहायक होते हैं।

ईको फ्रेंडली नवदुर्गा क्लब के संस्थापक महामंत्री राजाराम जैन कर्मयोगी ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज में मिट्टी की प्रतिमाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना एवं प्लास्टर ऑफ परिस्थित निर्मित प्रतिमाओं को जल में विसर्जित करने से रोकना और आने वाली पीढ़ियों में पर्यावरण सुरक्षा के संस्कार विकसित करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आस्था के साथ प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। श्री गणपति क्लब का यह अभिनव प्रयास पूरे समाज में पौधारोपण और पर्यावरण अनुकूल उत्सव मनाने के प्रति एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश देने में पूरी तरह सफल रहा है।

रावतभाटा में आज बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी

रावतभाटा, (निसं)। (शिव सिंह चौहान)। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय सहायक अभियंता रावतभाटा के अधीनस्थ बिजली तंत्र के आवश्यक रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के चलते गुरुवार, 15 अक्टूबर को शहर और ग्रामीण अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता देवेंद्र नागर ने बताया कि सुचारू विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 11 केवी न्यू मार्केट फीडर तथा 33 केवी लाइनों पर मेंटेनेंस का काम किया जाना अति आवश्यक है।

इसी मेंटेनेंस कार्य के चलते अलग-अलग समय में संबंधित क्षेत्रों में 4-4 घंटे का पावर कट रहेगा। सहायक अभियंता देवेंद्र नागर के अनुसार, 11 केवी न्यू मार्केट फीडर से जुड़े क्षेत्रों में प्रात: 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

इस दौरान कुमार मोहल्ला, मुर्गी फार्म, मानव मंदिर, ममता गार्डन, बुद्ध विहार और बीएसएनएल टावर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसके अतिरिक्त 33 केवी लाइन आरपीएस तथा 33 केवी एकलिंगपुरा लाइन पर आवश्यक रखरखाव कार्य किया जाएगा।

इसके चलते प्रात: 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक एकलिंगपुरा, बड़ोदिया, खातीखेडा, जालखेडा जीएसएस तथा पंप हाउस क्षेत्र की विद्युत सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। विद्युत विभाग और सहायक अभियंता देवेंद्र नागर ने संबंधित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे मेंटेनेंस अवधि को ध्यान में रखते हुए अपने बिजली व पानी से जुड़े आवश्यक कार्य निर्धारित समय से पूर्व निपटा लें तथा विभाग द्वारा किए जा रहे इस मेंटेनेंस कार्य में सहयोग प्रदान करें।

तुलाई के बाद नहीं उठा माल, सीजन में पहली बार मंडी हुई जाम, वाहनों की कतार लगी

कोटा, (निसं)। भामाशाह कृषि उपज मंडी कोटा के बाहर एक किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस कतार में ट्रक-ट्रॉली से लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली और छोटे वाहन तक शामिल हैं। सभी किसानों का माल लेकर मंडी में धुलाई के लिए पहुंचे थे, लेकिन मंडी में मंगलवार को हुई खरीद का माल नहीं उठा। ऐसे में इन वाहन चालकों को एंट्री नहीं मिली, इसी के चलते किसान परेशान हो रहे हैं। इनके साथ वाहन चालक भी शामिल हैं।

किसानों का कहना था कि वे सुबह 4 बजे से इंतजार कर रहे थे, लंबी लाईन लग गई। पहले सुबह 11 बजे एंट्री की बात कही थी। बाद में दोपहर 4 बजे

■ **मंडी में 3 लाख बोरी के आसपास माल आ रहा है, जबकि क्षमता 1 लाख बोरी की है**

और अब रात में 11 बजे की बात कही गई। भामाशाह कृषि उपज मंडी के सचिव मनोज कुमार मीणा का कहना था कि माल की आवक बढ़ रही है। व्यापारियों के माल का उठाव नहीं हो पाया है, मंडी में 3 लाख बोरी के आसपास माल आ रहा है जबकि क्षमता 1 लाख बोरी की है। ऐसे में अब किसानों के वाहनों की एंट्री की टाईमिंग सेट कर दी गई है। किसान संजय अग्रवाल का कहना था कि अचानक से गेट बंद कर दिए गए हैं। वह बूंदी जिले के इंद्रगढ़ से सुबह 3 बजे पहुंचे थे। अब 15 घंटे से ज्यादा समय से इंतजार कर लिया है।

किसान जुगराज का कहना था कि कुछ किसान अपनी पत्नी को लेकर भी पहुंचे थे, ऐसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली की आड़ में ही वह अपने परिवार के साथ बैठ गए। अधिकांश किसान आसपास आराम कर रहे हैं और कोई तो ट्रैक्टर पर ही सो रहा है।

किसान बंटी का कहना था कि यहां 1 किलोमीटर लंबी कतार है। बड़ी संख्या में वाहन फंस गए है। इस कतार में डेढ़ हजार वाहन है।

भवानीमंडी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सभा को संबोधित किया

भवानीमंडी, (निसं)। पंचायती राज्य चुनाव को लेकर बुधवार को कांग्रेस की भवानीमंडी में एक आम सभा को सम्बोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है जिसका नतीजा नगर निकाय के चुनाव में देखने को मिला है।

■ **भवानीमंडी आगमन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस स्वागत**

उन्होंने कहा दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के ग्रह क्षेत्र झालावाड़ जिले में अच्छा बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि राजा आये थे कि प्रथा खत्म हो गई है उन्होंने कांग्रेस संगठन को लेकर भी कहा कि आने वाले पंचायती राज्य चुनाव में पैराशूट वाले नेताओं के लिए जगह नहीं है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत कि है उनको ही अग्रिम पदों पर जगह दी जाएगी।उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के बाद उन्हें ढोलकी बजानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनके ही क्षेत्र में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली थी।

वहीं इससे पूर्व नेताप्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने कहा कि भाजपा कि केंद्र सरकार ने काला धन लाने कि बात कहीं थी वह काला धन तो नहीं लाये राजस्थान में नरेगा जैसी योजना बंद करके गरीबों के खाते खाली कर दिए उन्होंने कहा कि नगर पालिका चुनाव में जनता ने भाजपा को जवाब दे दिया अब पंचायती राज्य चुनाव में किसान भी जवाब दे देंगे।

सभा को खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर, विधायक, भेरुसिंह बापू, डग क्षेत्र से प्रत्याशी रहे चेतराज गहलोत, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर और भवानीमंडी ब्लॉक अध्यक्ष रोड सिंह परमार ने भी संबोधित किया।

सुल्तानपुर नगर पालिका ने करोड़ों की 14 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई

कोटा, (निसं)। नगर पालिका सुल्तानपुर के झोटोली गांव में करीब 14 बीघा पर अतिक्रमण को प्रशासन ने बुधवार को मुक्त करवाया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करीब 4 घंटे तक चली। इसके बाद प्रशासन ने जमीन का सीमाज्ञान करवाया और मौके पर नगरपालिका का बोर्ड लगाकर भूमि पर सरकारी स्वामित्व स्पष्ट किया।

■ **नगरपालिका अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और जमीन की नपाई की, इसमें यह जमीन नगरपालिका की होना सामने आया**



नगरपालिका सुल्तानपुर के झोटोली गांव में करीब 14 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया।

नगर पालिका सुल्तानपुर और कोटा ग्रामीण पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। नगर पालिका सुल्तानपुर के अधिशासी अधिकारी सुरेश रैगर ने बताया कि नगर पालिका सुल्तानपुर की जाटोली इलाके में तीन खसरों में 2.19 हेक्टेयर (करीब 14 बीघा) भूमि है। जिस पर लम्बे समय से अतिक्रमण हो रहा था। इस संबंध में नगर पालिका को शिकायत मिली थी। जिसके बाद नगर पालिका के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। इसकी नपाई भी की गई। इसमें यह जमीन नगर पालिका की होना सामने आया। इसके बाद कार्रवाई प्रस्तावित की गई।

कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में बुलडोजर और मशीनरी मौके पर लाई गई। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका, राजस्व विभाग और वन विभाग की टीम भारी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची।

यह अतिक्रमण ग्राम पंचायत के समय से लंबे समय से चल रहा था। अब इसे हटा दिया गया है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने सिवायचक और वन विभाग की जमीन पर किए गए कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लिया। अधिशासी अधिकारी के अनुसार रफीक पठान नाम के व्यक्ति ने अतिक्रमण किया हुआ था और यहां पर खेती की जा रही थी। उसे पहले नोटिस भी जारी किया गया था। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएसपी ओमप्रकाश सहरावग के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। मौके पर तीन थानों की पुलिस के साथ ग्रामीण पुलिस लाइन का जाप्ता भी मौजूद रहा। वहीं नायब तहसीलदार संदीप मेघवाल को कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया।

फसल अवशेष जलाने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी

कोटा, (निसं)। फसल कटाई के उपरान्त फसल अवशेषों को जलाना प्रतिबंधित किया गया है। फसल अवशेष जलाने की दुष्परिणामों को देखते हुए किसानों से अपील की गई है कि वे पराली न जलाएं, भूसा या बेल्स (गट्ठर) बनाएं अन्यथा फसल अवशेष जलाने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।

संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फसल अवशेषों को जलाने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में भ



अभिषेक शर्मा में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल जैसी क्षमता है और टी20 क्रिकेट में उनके प्रदर्शन को लंबे समय तक याद रखा जाएगा।
- चेतेश्वर पुजारा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर, अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी



शिखर धवन

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप में अपनी भागीदारी को लेकर सामने आई खबरों पर सफाई देते हुए कहा कि आयोजकों ने उनकी जानकारी और अनुमति के बिना उनके नाम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में उनकी टीम उचित कानूनी कदम उठाएगी। धवन ने मीडिया और प्रशंसकों से अनधिकृत घोषणाओं पर भरोसा नहीं करने की अपील भी की। मैंने वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप में प्रतिभागी के रूप में अपना नाम देखा है। आयोजकों ने मेरी जानकारी या अनुमति के बिना मेरे नाम का इस्तेमाल किया है।

क्या आप जानते हैं ?... हॉकी का गोल्डन डबल : पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा।

विंडीज ने चौथा मैच जीतकर सीरीज की बराबर, भारत नहीं बना पाया 248 रन

हैदराबाद, 14 अक्टूबर। वेस्टइंडीज ने भारत को चौथे टी20 मैच में 24 रन से हराया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 247 रन बनाए। कप्तान शे होप ने शतक लगाया। इसके जवाब में भारतीय टीम 19.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 223 रन ही बना सका। भारत के लिए संजू सैमसन ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से कीमो पॉल ने 5 विकेट चटकाए।

वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 मैच में शे होप के शतक की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 247 रन बनाए। टीम के लिए शे होप ने सर्वाधिक रन (102) बनाए। भारत के लिए अक्षर पटेल, अर्शदीप और प्रिंस यादव को सफलता मिली। इसके जवाब में भारत ने 5वें ओवर में संजू सैमसन का विकेट गंवाया। संजू ने 23 गेंद में 56 रन बनाए। ईशान किशन 6 रन ही बना सके। कीमो पॉल ने पारी के 5वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को आउट किया। अभिषेक शर्मा 24 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हुए। नमन धीर बिना खाता खोले आउट हुए। तिलक वर्मा ने 25 गेंद में 43 रन बनाए, उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ 32 गेंद में 70 रन की साझेदारी की। नीतीश कुमार रेड्डी ने 20 गेंद में 41 रन बनाए। प्रिंस खाता नहीं खोल सके और अक्षर पटेल ने तीन रन बनाए।

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज को 5वें ओवर में झटका लगा। सलामी बल्लेबाज एंड्रयू ने 16 गेंद में 21 रन बनाए। अक्षर पटेल ने उन्हें आउट किया। प्रिंस यादव ने 9वें ओवर में शिमरन हेटमायर को पवेलियन भेजा। होप और हेटमायर के बीच दूसरे विकेट के लिए 24 गेंद में 58 रन की साझेदारी हुई। प्रिंस यादव को सफलता मिली। रोवमैन पावेल ने 17 गेंद में 24 रन बनाए। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौथे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वेस्टइंडीज ने दो बदलाव किए हैं, जबकि भारत पिछली टीम के साथ उतरा है। वेस्टइंडीज की टीम में कामिल पूरन की जगह ज्वेल ऐंड्रयू की वापसी हुई है, जबकि सैंपसन की जगह रोमारियो शेफर्ड को मौका मिला है। भारतीय टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक बार फिर सीरीज कब्जा करने के काफी करीब है।



नटराजन की एसआरएच में वापसी, डीसी ने अंसारी के बदले किया आईपीएल ट्रेड

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक प्लेयर ट्रेड में तेज़ गेंदबाज़ टी. नटराजन को वापस अपनी टीम में शामिल किया है, जबकि लेग-स्पिनर ज़ीशान अंसारी दिल्ली कैपिटल्स की टीम में चले गए हैं। चेन्नई के इस तेज़ गेंदबाज़ ने 2020 से 2024 तक एसआरएच के लिए खेला और 2024 में 19 विकेट लिए, जो उस सीज़न में किसी भी एसआरएच गेंदबाज़ द्वारा लिए गए सबसे ज़्यादा विकेट थे। इस बीच, नटराजन को 2025 की नीलामी में डीसी ने 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। अब वह 5 करोड़ रुपये की बदली हुई फीस पर एसआरएच में शामिल हो रहे हैं। अंसारी ने 10 मैचों में छह विकेट लिए और वह अपनी मौजूदा 40 लाख की फीस पर डीसी में शामिल हो रहे हैं।

वित्तीय अनियमितताओं का आरोप, बीएफआई के महासचिव प्रमोद निलंबित

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने महासचिव प्रमोद कुमार को कथित तौर पर अधिकारों के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं और जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने के आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यह अंतरिम निलंबन है और इसे आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा। बीएफआई की ओर से जारी बयान के अनुसार महासंघ के संविधान की धारा 24 के उपखंड 16 और धारा 24 के उपखंड 36 के तहत यह कार्रवाई की गई है। प्रमोद कुमार पर अधिकारों के खुले दुरुपयोग, जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने, जांच में सक्रिय रूप से बाधा डालने और वित्तीय अनियमितताओं तथा अनुचित आचरण के अस्पष्ट मामलों के आरोप लगाए गए हैं।

चैंपियनशिप रद्द होने की जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप - मंगलवार को जारी पत्र में प्रमोद कुमार पर हिमाचल प्रदेश के नाहन में 16 से 23 अगस्त तक प्रस्तावित बीएफआई एलीट पुरुष एवं महिला ओपन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 को रद्द किए जाने के मामले की जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया गया है। पत्र में कहा गया है कि वह महासंघ की ओर से आयोजित प्रतियोगिताओं और उसकी प्रतिष्ठा पर असर डालने वाले गंभीर मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन पर स्वतंत्र जांच को डराने और बाधित करने के उद्देश्य से कथित तौर पर अवैध और दुर्भावनापूर्ण नोटिस जारी करने का आरोप भी लगाया गया है।

पार्थिव पटेल ने मिस की बीसीसीआई की डेडलाइन

क्या मुख्य चयनकर्ता पद की दौड़ से हुए बाहर ?



नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। भारत के पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल, जिन्हें बीसीसीआई के पुरुषों की टीम के मुख्य चयनकर्ता के तौर पर अजीत अगरकर की जगह लेने का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, उन्होंने अभी तक इस पद के लिए आवेदन नहीं किया है। बीसीसीआई ने इस खाली पद के लिए 6 अक्टूबर को आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी और आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर को शाम 5 बजे तय की गई थी। पटेल ने तब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया था और अब वे ऐसा तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक बोर्ड आवेदन की समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ाता। फिलहाल, साउथ ज़ोन के सेलेक्टर प्रज्ञान ओझा अंतरिम चीफ सेलेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कमेटी में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। अभी के हिसाब से, पार्थिव के सीनियर सिलेक्शन पैनल में शामिल होने के बजाय गुजरात टाइटंस के कोचिंग सेटअप और अपने ब्रॉडकास्टिंग के काम में बने रहने की संभावना है, जबकि ओझा के चीफ सेलेक्टर के तौर पर अपना बाकी कार्यकाल पूरा करने की उम्मीद है।

बीसीसीआई ने 6 अक्टूबर को जारी अपने बयान में कहा था कि नया सेलेक्टर टेस्ट, वनडे और टी20 के लिए भारतीय टीमों को चुनने, उभरते हुए टैलेंट की पहचान करने और बेंच स्ट्रेंथ मज़बूत करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। इस भूमिका में घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ियों की खोज करना, टीम मीटिंग में शामिल होना, मैचों के लिए यात्रा करना और बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल को हर तिमाही परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने वाली रिपोर्ट सौंपना भी शामिल होगा।

योग्यता के नियमों के अनुसार, आवेदकों ने कम से कम सात टेस्ट मैच, 30 फर्स्ट-क्लास मैच, या 10 वनडे और 20 फर्स्ट-क्लास मैच खेले होने चाहिए। साथ ही, उम्मीदवारों को कम से कम पांच साल पहले क्रिकेट से रिटायर हो जाना चाहिए था। माना जा रहा है कि नया सदस्य वेस्ट ज़ोन से होगा, जहाँ से अगरकर आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के रहने वाले भारत की महिला टीम के पूर्व कोच रमेश पोवार, जिनके जूनियर पुरुष चयन समिति की कमान संभालने की उम्मीद थी, अब वेस्ट ज़ोन से सीनियर चयनकर्ता के पद के लिए दावेदार हो सकते हैं।

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रेनशॉ और हेजलवुड को फायदा, टी-20 में श्रेयस चौथे स्थान पर

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू रेनशॉ और जोश हेजलवुड को आईसीसी की ताजा पुरुष टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में फायदा हुआ है। भारत के श्रेयस अय्यर ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में करियर का सर्वश्रेष्ठ चौथा स्थान हासिल कर लिया है।

आईसीसी के अनुसार डरबन टेस्ट की पहली पारी में 190 रन बनाने वाले रेनशॉ ने दूसरी पारी में भी 82 रन की अहम पारी खेली। उनके इस प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को मैच में मजबूत स्थिति हासिल करने में मदद मिली। रेनशॉ टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 100 से बाहर रहने के बाद संयुक्त रूप से 49वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन चार स्थान ऊपर चढ़कर 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम ने भी चार स्थान की छलांग लगाई और संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर पहुंच गए।



हेजलवुड गेंदबाजी रैंकिंग में सातवें स्थान पर

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने डरबन टेस्ट के अंतिम दिन 49 रन देकर छह विकेट लिए थे। इस प्रदर्शन के बाद वह टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया तीन साल से अधिक समय बाद अपना पहला टेस्ट खेलने के बाद गेंदबाजी रैंकिंग में लौट आए हैं। वह 34वें स्थान पर हैं। भारत के रवींद्र जडेजा टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि साइमन हार्मर ने पांच स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 23वां स्थान हासिल किया है।

रणजी ट्रॉफी : पहली पारी में असफल रहने के बाद करुण नायर ने लगाया नाबाद शतक

विजयवाड़ा, 14 अक्टूबर। कर्नाटक के अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर ने आंध्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में पहली पारी की नाकामी से उबरते हुए शानदार शतक जड़ा। बुधवार को पहली पारी में केवल आठ रन बनाने वाले 34 वर्षीय नायर ने दूसरी पारी में दमदार बल्लेबाजी करते हुए रणजी ट्रॉफी में अपना 20वां शतक पूरा किया।

नायर ने अपनी लय हासिल करते हुए बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज सौरभ और ललित मोहन के खिलाफ शानदार छक्के लगाए। उन्होंने गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचाकर अपने आक्रामक अंदाज की झलक दिखाई। पहली पारी में कम स्कोर के बाद उनका यह शतक उनकी बल्लेबाजी क्षमता का प्रभावशाली उदाहरण रहा।

स्पीकर देवनानी ने रॉयल राजस्थान स्टेट कराटे चैम्पियनशिप के प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया



जयपुर, 14 अक्टूबर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से बुधवार को यहां विधानसभा में कराटे के नौ खिलाडियों ने मुलाकात की। ये खिलाडी रॉयल राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप में भाग लेकर लौटे है। देवनानी ने रॉयल राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप में खिलाडियों को मिले प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया। देवनानी ने बच्चों को भविष्य में निरन्तर सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। देवनानी ने खिलाडियों से संवाद करते हुए खेलों के प्रति उनकी रुचि और कराटे के अभ्यास के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने खिलाडियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और संघर्ष करने की क्षमता विकसित होती है। कराटे जैसे आत्मरक्षा के खेल बच्चों को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के साथ ही मानसिक दृढ़ता भी प्रदान करते हैं। देवनानी ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ खेल गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए।

गांगुली, रहाणे, लारा और रूट ने प्रिंस विलियम के साथ खेला टेनिस बॉल क्रिकेट

लंदन, 14 अक्टूबर। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और अजिंक्य रहाणे सहित क्रिकेट जगत की कई दिग्गज हस्तियों ने लंदन में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट का मैत्रीपूर्ण मुकाबला खेला। इस खास आयोजन का उद्देश्य क्रिकेट के प्रति भारत और ब्रिटेन के साझा जुनून का जश्न मनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। यह आयोजन अगले महीने मुंबई में होने वाले अर्थशॉट पुरस्कार समारोह की उलटी गिनती के तहत किया गया। द रॉयल फाउंडेशन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह मुकाबला बकिंघम पैलेस के बाहर स्थित द मॉल मार्ग पर खेला गया।



जनरल अमर सिंह कानोता कप : रामबाग-चांदना पोलो की एकतरफा जीत

धनखड़ ने दागे 4 गोल, कानोता / मेफेयर को 9.5-3 से हराया

जयपुर, 14 अक्टूबर। जयपुर पोलो सीजन 2026 के अंतर्गत राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर खेले गए जनरल अमर सिंह कानोता कप (06 गोल्स) के मुकाबले में टीम रामबाग-चांदना पोलो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कानोता/मेफेयर पोलो को 9.5-3 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। विजेता टीम की ओर से डीनो धनखड़ ने सर्वाधिक 4 गोल दागे, जबकि जॉन जोस अल्बर्डी ने 3 और अशोक चांदना ने 2 गोल किए। टीम को शुरुआत में आधे गोल की बढ़त भी मिली थी। आरके सिद्धांत सिंह ने भी टीम का प्रतिनिधित्व किया। कानोता/मेफेयर पोलो की ओर से शमशीर अली, प्रताप सिंह कानोता और अनय शाह ने एक-एक गोल किया। टीम में जयवीरसिंह गोहिल भी शामिल रहे।

रामबाग-चांदना और आरपीसी के बीच पहला सेमीफाइनल आज - टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल गुरुवार को टीम रामबाग-चांदना पोलो और टीम आरपीसी के बीच खेला जाएगा। मुकाबला पीपीसी ग्राउंड नंबर-1 पर शाम 4:30 बजे शुरू होगा।

लोसल में 21 से राज्य सब-जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप, 400 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग

जयपुर, 14 अक्टूबर। राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में राजस्थान स्टेट सब-जूनियर (अंडर-11 व अंडर-13 बालक-बालिका) बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 का आयोजन 21 से 25 अक्टूबर तक सीकर जिले के लोसल में किया जाएगा। प्रतियोगिता के मुकाबले सीकर रोड स्थित शेखावाटी पब्लिक स्कूल परिसर में खेले जाएंगे, जिसमें प्रदेश के 400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव के.के. शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता के क्वालीफाइंग मुकाबले 20 व 21 अक्टूबर को होंगे, जबकि मुख्य ड्रॉ के मुकाबले 22 अक्टूबर से शुरू होंगे। प्रतियोगिता में अंडर-11 व अंडर-13 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं के एकल एवं युगल मुकाबले आयोजित किए जाएंगे।

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के आधार पर आगामी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए राजस्थान टीम का चयन किया जाएगा। खिलाड़ियों की सुविधा और मुकाबलों का समय पर संचालन सुनिश्चित करने के लिए आयोजन स्थल पर कम से कम चार कोर्ट तैयार किए गए हैं।

आयोजन समिति के अध्यक्ष भंवर लाल रिणवा और आयोजन सचिव सुशील स्वामी के नेतृत्व में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए त्रिलोक शुक्ला को मुख्य निर्णायक तथा विनीत शर्मा को मैच कंट्रोलर नियुक्त किया गया है। लोसल में 21 अक्टूबर से राज्य सब-जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, 400 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग

रणंजय सिंह की कप्तानी में जीता रजत पदक

जयपुर, 14 अक्टूबर। राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय सब-जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 में तेलगाना के आरोग्य खिलाड़ियों को खिलाने पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किया जुर्माना और राजस्थान का हुआ प्रमोशन। राजस्थान फुटबॉल के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। लगभग 34 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान की सब-जूनियर फुटबॉल टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया है। वर्ष 1991-92 के बाद मिली इस ऐतिहासिक सफलता के साथ राजस्थान ने राष्ट्रीय सब-जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के टियर-1 में भी स्थान प्राप्त कर लिया है।



अंडर-23 राष्ट्रीय एथलेटिक्स का कल से आगाज, राजस्थान के 156 एथलीट दिखाएंगे दम

जयपुर, 14 अक्टूबर। गुलाबी नगरी में शुक्रवार से देश के उभरते एथलीटों का जमावड़ा लगेगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में 16 से 18 अक्टूबर तक छठी इंडियन ओपन अंडर-23 राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें देशभर से एक हजार से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मेजबान राजस्थान की ओर से 156 सदस्यीय दल मैदान में उतरेगा। कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके एथलीट भी प्रतियोगिता में अपनी चुनौती पेश करेंगे। राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव देवनारायण गुर्जर ने बताया कि प्रतियोगिता में पुरुष एवं महिला वर्ग की कुल 40 स्पर्धाएं होंगी। तीन दिन में 40 स्वर्ण सहित कुल 120 पदकों के लिए मुकाबले खेले जाएंगे। उत्तर प्रदेश 244 खिलाड़ियों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में भाग लेगा, जबकि राजस्थान 156 सदस्यों के साथ दूसरे स्थान पर रहेगा। हरियाणा के 122 एथलीट भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की टीमें भी चुनौती पेश करेंगी।

10 हजार मीटर दौड़ से होगी शुरुआत - आयोजन सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर के अनुसार, प्रतियोगिता के पहले दिन सुबह 6:30 बजे पुरुष एवं महिला वर्ग की 10,000 मीटर दौड़ से मुकाबलों का आगाज होगा।

तारीक क्रिकेट अकादमी ने सात रन से जीता रोमांचक मुकाबला

रोहन बने मैन ऑफ द मैच, गेंदबाजी में झटके 3 विकेट



जयपुर, 14 अक्टूबर। सोनी क्रिकेट स्टेडियम पर खेले जा रहे प्रथम कर्नल बिशन सिंह राठौड़ क्रिकेट टूर्नामेंट में तारीक क्रिकेट अकादमी ने कैंडलविक क्रिकेट अकादमी को रोमांचक मुकाबले में सात रन से हराया। तारीक क्रिकेट अकादमी की जीत में रोहन सिंह ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए तारीक क्रिकेट अकादमी की टीम 28.3 ओवर में 135 रन पर ऑलआउट हो गई। तवीश शर्मा ने 50 और रोहन सिंह ने 29 रन बनाए। कैंडलविक की ओर से आर्यमन सिंह ने चार और वत्सल शर्मा ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए कैंडलविक क्रिकेट अकादमी की टीम 33.1 ओवर में 128 रन पर सिमट गई। हर्षित कुमावत ने 27 और दक्ष पारीक ने 23 रन बनाए। तारीक क्रिकेट अकादमी की ओर से रोहन सिंह और राशिद ने तीन-तीन, जबकि अयान ने दो विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई।

14वां महाराजा सवाई भवानी सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट 2 नवम्बर से

आठ खेलों में अंडर-19 बॉयज एवं गर्ल्स वर्ग के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

जयपुर, 14 अक्टूबर। महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल, जयपुर की मेजबानी में 14वें महाराजा सवाई भवानी सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन 2 से 5 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। चार दिवसीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के युवा खिलाड़ी अंडर-19 बॉयज एवं गर्ल्स वर्गों में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

टूर्नामेंट में बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, पिकलबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल और शतरंज सहित आठ खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस आयोजन का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक मंच प्रदान करना और उनमें खेल भावना एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन की भावना को प्रोत्साहित करना है।

रणजी में राजस्थान को पहली पारी की बढ़त, मैच ड्रॉ

महिपाल लोमरोर शतक से चूके, अजय सिंह कुकना बने प्लेयर ऑफ द मैच

जयपुर, 14 अक्टूबर। राजस्थान क्रिकेट संघ की मेजबानी में सवाई मानसिंह स्टेडियम पर राजस्थान और तमिलनाडु के बीच खेला गया रणजी ट्रॉफी मुकाबला ड्रॉ समाप्त हुआ। राजस्थान ने पहली पारी में 89 रन की बढ़त के आधार पर महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। शानदार प्रदर्शन के लिए राजस्थान के अजय सिंह कुकना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि दूसरी पारी में महिपाल लोमरोर 84 रन बनाकर शतक से चूक गए। राजस्थान ने पहली पारी में 363 रन बनाए, जिसके जवाब में तमिलनाडु की टीम 274 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में राजस्थान ने छह विकेट पर 192 रन बनाकर पारी घोषित की। महिपाल लोमरोर ने 84, कार्तिक शर्मा ने 42 और अजय सिंह कुकना ने नाबाद 32 रन बनाए। तमिलनाडु के साई किशोर ने तीन विकेट लिए। जीत के लिए मिले लक्ष्य के जवाब में तमिलनाडु ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 73 रन बनाए। जगदीशन 42 और साई सुदर्शन 26 रन बनाकर नाबाद रहे।







अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफीः अतुल जायसवाल का शतक, हिमाचल 251/6

हिमाचल प्रदेश के अम्तर में राजस्थान और हिमाचल के बीच खेले जा रहे अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी मुकाबले के तीसरे दिन राजस्थान ने पहली पारी में 488 रन बनाए। जवाब में हिमाचल ने छह विकेट पर 251 रन बना लिए। हिमाचल की ओर से अतुल जायसवाल 107 रन बनाकर नाबाद हैं। राजस्थान के गेंदबाज आयुष अमेरिया ने 60 रन देकर तीन विकेट लिए।

अंडर-19 वीनू मांकड़ ट्रॉफीः रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद जीता

अंडर-19 वीनू मांकड़ ट्रॉफी में राजस्थान को हैदराबाद के खिलाफ एक विकेट से हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन पर आउट हो गई। आराध्य अग्रवाल ने नाबाद 53, रजत बघेल ने 44, अभय शर्मा ने 37 और कुशाग्र ओझा ने 26 रन बनाए। हैदराबाद के वेद रेड्डी ने तीन और यशवीर गौड़ ने दो विकेट लिए। जवाब में हैदराबाद ने नौ विकेट पर 194 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। यशवीर गौड़ ने नाबाद 94 और आदित्य जव्वाजी ने 51 रन की अहम पारियां खेलीं। राजस्थान की ओर से सौभाग्य सिंह भाटी ने पांच विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि सुमीत सैनी ने तीन विकेट झटके।

अंडर-19 महिला टी-20 ट्रॉफीः राजस्थान की शानदार जीत, धृति माथुर चमकीं

अंडर-19 महिला टी-20 ट्रॉफी में राजस्थान ने केरल को नौ विकेट से हराया। केरल की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 85 रन पर आउट हो गई। राजस्थान की ओर से निष्ठा सोती ने 19 रन देकर चार विकेट झटके, जबकि प्रीत कपूर ने दो विकेट लिए। वंशिका और पलक को एक-एक सफलता मिली। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने एक विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की। धृति माथुर ने 66 गेंदों पर 13 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 85 रन बनाए। प्रियांशी चौधरी ने 31 और अंशिका ने नाबाद 12 रन का योगदान दिया। धृति की शानदार बल्लेबाजी और निष्ठा की घातक गेंदबाजी राजस्थान की जीत की प्रमुख वजह रहीं।

लक्षित की घातक गेंदबाजी, द राजस्थान क्रिकेट अकादमी जीती



जयपुर, 14 अक्टूबर। अंडर-14 मानसून कप क्रिकेट प्रतियोगिता में द राजस्थान क्रिकेट अकादमी ने एसएचएस क्रिकेट अकादमी को छह विकेट से हराकर जीत दर्ज की। एसएचएस क्रिकेट अकादमी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 37.4 ओवर में 150 रन पर ऑलआउट हो गई। नीरव सैनी ने 28, अंश चतुर्वेदी ने 25 और योगित यादव ने 23 रन बनाए। द राजस्थान क्रिकेट अकादमी की ओर से लक्षित ने चार और देव शर्मा ने तीन विकेट झटके। जवाब में द राजस्थान क्रिकेट अकादमी ने ध्रुव सिंह के 53 और कार्तिक के 32 रनों की बदौलत 32.4 ओवर में चार विकेट पर 151 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। शानदार गेंदबाजी करने वाले लक्षित कोमैन ऑफ द मैचचुना गया।

प्रधानमंत्री की 25 वर्ष की जन सेवा पर राजस्थान मंत्रिमंडल ने अभिनंदन किया

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म व ट्रांसफॉर्म की नई संस्कृति स्थापित की है

जयपुर, 14 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 25 वर्षों की अनवरत जनसेवा के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्टूबर को सरकार के मुखिया के रूप में राष्ट्रसेवा का ऐतिहासिक पड़ाव पूरा किया है। इस उपलक्ष्य में राजस्थान मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं को प्रधानसेवक मानकर देश में "रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म" की नई संस्कृति स्थापित की है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक एवं ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक निर्णयों से देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुभव और विज़न का लाभ राजस्थान की डबल इंजन सरकार को भी मिल रहा है। प्रदेश में 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे विकसित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश 39.36 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के साथ अग्रणी प्रदेश बन चुका है। इस तरह राजस्थान देश में सौर ऊर्जा में प्रथम एवं अक्षय ऊर्जा स्थापना में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक ली।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा और गौरवपूर्ण उपस्थिति में दिसंबर 2024 में "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट" हुआ। इसमें 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने प्रदेश को पचपदरा में देश की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज-2 और माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुभव व विज़न का लाभ राजस्थान को मिल रहा है। प्रदेश में 2750 किलोमीटर लंबे 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे तथा जयपुर रिंग रोड का निर्माण केन्द्र सरकार के सहयोग से हो रहा है।**

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन, सहयोग और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा भी उपस्थित थे।

प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए छात्रों के साथ पुलिस ने मारपीट की- राहुल गांधी

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों के साथ कथित मारपीट का मुद्दा उठाया है। राहुल ने बुधवार को कुछ प्रदर्शनकारियों को मीडिया के सामने पेश किया, जिन्होंने पुलिस हिरासत में उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किए जाने के आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को अपने साथ हुई घटनाओं के वीडियो और अन्य साक्ष्य सुरक्षित रखने चाहिए, ताकि मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

- **राहुल गांधी ने कुछ भुक्तभोगी आंदोलकारियों को मीडिया के सामने पेश किया।**

केरल की छात्रा अथिरा ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान बस में महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी के बारे में पूछने पर उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने दावा किया कि कनॉट प्लेस थाने के सामने उन्हें पीटा गया, जिससे उनकी आंख और कान में चोट आई। अथिरा के अनुसार, उनके एक कान से सुनाई देना बंद हो गया है। बांसुरी वादक समर ने भी हिरासत में मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पांच अक्टूबर और फिर 11 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लिया गया था। समर के मुताबिक, सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की।

'अमेरिका में रह रही दुष्कर्म पीड़िता को जांच में सहयोग के लिए नोटिस तामील कराएं'

राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2005 में भारत-अमेरिका के बीच लागू पारस्परिक कानूनी सहायता व्यवस्था के तहत नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया अपनाई जाए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 14 अक्टूबर। दुष्कर्म प्रकरण में पीड़िता जब जांच में सहयोग के लिए उपलब्ध नहीं हुई और पुलिस को उसके संबंधियों से मालूम चला कि वह अमेरिका चली गई है। ऐसे में पुलिस जांच आगे कैसे बढ़ाई जाए, इस संदर्भ में बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह व विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि अमेरिका में रह रही दुष्कर्म पीड़िता का मौजूदा एड्रेस पता लगाकर उसे नोटिस तामील करवाएं। अदालत ने अनुसंधान अधिकारी को कहा है कि वह 21 दिनों में गृह मंत्रालय को पीड़िता के पासपोर्ट की जानकारी सहित पूरी डिटेल्स, समन की दो कॉपी सहित भेजें। अदालत ने पालना रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए आगामी सुनवाई आठ सप्ताह बाद तय की है। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश मामले में आरोपी बनाए गए चन्द्रभूषण सिंह की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- **हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीड़िता मुख्य गवाह है और उसकी भागीदारी के बिना जांच प्रभावी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए न्यायपूर्ण सुनवाई के लिए पीड़िता को नोटिस या समन की प्रभावी तामील होना जरूरी है।**

इस मामले में पीड़िता ने वर्ष 2022 में एफआईआर दर्ज करायी थी, परंतु पुलिस ने जब प्रकरण की जांच शुरू की तो पीड़िता का कोई अता-पता नहीं लगा। जांच की डायरी जब हाईकोर्ट में अनुसंधान अधिकारी ने पेश की तो उसमें दो तथ्य सामने आये कि, 1 जुलाई 2022 को ही पीड़िता अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन आई थी और आवेदन दिया कि मैंने गुस्से में आकर परिवाद किया था, इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की जाए। परंतु जब एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ने पीड़िता से 24 नवंबर 2022 को फोन पर बात की तो पीड़िता ने कहा कि मामले की जांच बंद करने का आवेदन उसने दबाव में दिया था और वह जांच बंद नहीं करना चाहती। परंतु इन विरोधाभासी बयानों के कारण जांच अधिकारी ने मामले में एफ.आर. लगाने की सिफारिश की थी, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों की वजह से मामले में एफ.आर नहीं लगी।

अदालत ने 3 सितंबर 2024 को पीड़िता को नोटिस जारी किया था, लेकिन पिछले दो सालों से नोटिस तामील नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि परिवादिया के परिजनों से उसका अमेरिका में रहने का पता चला है, परंतु पूरा पता व संपर्क नंबर ज्ञात नहीं हैं।

वहीं आरोपी के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि चन्द्रभूषण सिंह के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि वर्ष 2005 में लागू समझौते के तहत वह अमेरिका में समन तामील करवा सकते हैं। जिस पर अदालत ने केन्द्र सरकार को भारत-अमेरिका के बीच लागू पारस्परिक कानूनी सहायता व्यवस्था के तहत नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया अपनाने और पीडिता का मौजूदा पता लगाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीडिता मुख्य गवाह है और उसकी भागीदारी के बिना जांच प्रभावी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए न्यायपूर्ण सुनवाई के लिए पीडिता को नोटिस या समन की प्रभावी तामील होना जरूरी है।

अदालती आदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साल इसी तरह अभ्यर्थियों को पहली काउंसलिंग में शामिल कर कॉलेज का आवंटन किया जाता है। इसी वर्ग में रजिस्ट्रेशन के बाद भी प्रार्थी का नाम 19 सितंबर की सूची में नहीं था। इसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 24 सितंबर को अस्थाई तौर पर याचिकाकर्ता के दस्तावेज सत्यापन कराने व काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता अदालती आदेश की पालना में 26 सितंबर को काउंसलिंग चेयरमैन के समक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन फिर भी उसे शामिल नहीं किया, जिसे अवमानना याचिका के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश की अवमानना करने वालों को दंडित किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

हाइजैक अलर्ट के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यात्रियों को सुरक्षित उतारकर टर्मिनल में बैठाया गया। दिल्ली से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की टीम को भी सतर्क रखे जाने की जानकारी सामने आई।

सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की जांच की। शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद विमान के रखरखाव से जुड़े इंजीनियरों को भी मौके पर बुलाया गया। शुरुआत में ऐसी जानकारी सामने आई कि पायलट ने गलती से अलर्ट बटन दबा दिया था और कुछ ही सेकंड में संकेत बंद कर दिया गया था। बाद में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण अलर्ट संदेश जनरेट होने की आशंका है। हालांकि, पायलट ने पूछताछ के दौरान गलती से बटन दबाने की बात से इनकार किया। इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) पूरे मामले की जांच करेगा। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि हाईजैक का संकेत देने वाला 7500 कोड किस वजह से सक्रिय हुआ और इसका संदेश एटीसी तक कैसे पहुंचा। घटना की पुष्टि करते हुए एयर इंडिया ने कुछ घंटे बाद जारी बयान में कहा कि उड़ान को सुरक्षा संबंधी संभावित चिंता के कारण डायवर्ट किया गया था। एयरलाइन के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा जांच की गई और इसके बाद उन्हें दिल्ली के लिए उड़ान जारी रखने हेतु दोबारा विमान में सवार होने की अनुमति दी गई। विमान को दोपहर 2:24 पर नई दिल्ली रवाना कर दिया गया।

शाह ने कांग्रेस पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध स्थल सूची से हटाना... पहले वोट की चोरी और फिर "विरोध करने के अधिकार की चोरी"-यह भाजपा की तानाशाही का सबूत है।" उन्होंने आगे कहा, "ज्ञानेश कुमार को बचाना बंद करो!"

खड़गे ने कहा कि सरकार पर सवाल उठाने वालों को जेल में डाला जा रहा है, युवा प्रदर्शनकारियों को पीटा जा रहा है और हिरासत में लिया जा रहा है। महिलाओं को पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है, जबकि "आरएसएस के गुंडों" को बिना किसी कार्रवाई के छूट मिली हुई है।

राजनीतिक मामलों के अनुभवी पर्यवेक्षकों का कहना है कि शाह इस समय बेहद मुश्किल स्थिति में हैं। उनके अनुसार, वे चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मैदान छोड़कर पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। इससे सत्ताधारी दल के लिए उन्हें बचाने का रास्ता खुला हुआ है। पर्यवेक्षकों ने कहा कि इससे जनता के बीच बहुत गलत संदेश जा रहा है।

एयर फ्रांस ने इज़रायल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं। पाकिस्तान सहित, 31 देशों के एयरलाइन क्रू पर एयर फ्रांस के प्रतिबंध के बाद, शिकागो स्थित यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी अपने पायलटों और केबिन क्रू को इज़रायल आने-जाने वाली उड़ानों के लिए राष्ट्रीयता आधारित नियमों के बारे में जानकारी दी है। इन प्रतिबंधों ने अंतरराष्ट्रीय विमानन पर पड़ने वाले असर और, क्या अन्य एयरलाइन्स भी इज़रायल के नियमों का पालन करने के लिए ऐसा ही करेंगी, इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

फ्रांस की खोजी समाचार वेबसाइट मीडियापार्ट और विमानन खुफिया कंपनी सीएच-एविएशन की 13 अक्टूबर की रिपोर्टों के अनुसार, दोनों विमानन कंपनियों ने अपने पायलटों और केबिन क्रू को इज़रायल द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की जानकारी दी है। एयर फ्रांस ने पुष्टि की है कि वह इन नियमों का पालन कर रही है, जबकि खबरों के अनुसार, यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी इन प्रतिबंधों को अपने चालक दल की ड्यूटी तय करने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया है।

चैक गणराज्य की सबसे बड़ी विमानन कंपनी स्मार्टविंग्स ने भी पुष्टि की है कि वह इज़रायल के प्रतिबंधों का पालन करेगी। हालांकि, कंपनी ने कहा कि अब तक उसके चालक दल की ड्यूटी तय करने और उड़ानों के संचालन पर इन प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ा है।

वाहनों पर काली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिका के तौर पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। अदालत ने कहा कि यह मामला व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है। अदालत ने डेथ रेफरेंस से जुड़े मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि अपीलार्थियों की ओर से काले रंग की कार में पीड़िता का शव ले जाया गया। जिससे राहगीरों के लिए अंदर देखना असंभव हो गया और आरोपियों को शव को अपराध स्थल से दूर स्थान पर ठिकाने लगाने में सुविधा हुई। अदालत के समक्ष बार एसोसिएशन के सदस्यों ने वाहनों पर काली फिल्म लगाने पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में चार पहिया वाहन काले शीशों अथवा रंगीन शीशों के साथ चलाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के जारी निर्देशों और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के प्रावधानों के खिलाफ है। वकीलों ने विशेष तौर पर निजी एम्बुलेंसों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि उनमें से अधिकांश में काले रंग के शीशे लगे हुए हैं। इस बारे में पूर्व में प्रकाशित खबरों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा था कि काले रंग के शीशों वाली निजी एम्बुलेंसों का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

सीजेपी के सौरव दास व आशुतोष रांका न्यायिक हिरासत में

- **पुलिस ने उन्हें 13 अक्टूबर को प्रतिबंधित जंतर मंतर पर पहुँचने व पुलिस के काम में बाधा डालने पर गिरफ्तार किया।**

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मामले में काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दो नेताओं को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सौरव दास और आशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे सहित 14 सदस्यों के खिलाफ कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अलग-अलग दो एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर को सीजेपी के ये सदस्य प्रतिबंधित जंतर-मंतर पर निजी परिसर के रास्ते पहुंचे और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली। इसके बाद पुलिस ने तीनों नेताओं को हिरासत में लिया था। तीनों को आज सुबह स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि अजिंक्य शिंदे को छह महीने तक शांति बनाए रखने के लिए 5,000 रुपये के मुचलके पर पाबंद किया गया। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को आधिकारिक विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। इसका मतलब है कि जंतर-मंतर पर कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता।

राहुल गांधी धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के परिवार से मिले

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार रात इंडिया गेट पहुंचे और वहां धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात की। अंकिता के परिवार ने दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने के भाजपा के फैसले का विरोध किया है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर इस फैसले को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा कब तक बलात्कारियों के साथ खड़ी रहेगी?

युवा कांग्रेस ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर-मंतर मार्च निकाला

- **एनएसयूआई ने अपनी महिला कार्यकर्त्ताओं के साथ कथित मारपीट पर एफआईआर की मांग की।**

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। भारतीय युवा कांग्रेस ने बुधवार को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार बहाल करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च निकाला। वहीं, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने अपनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बताया कि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने का मौखिक आश्वासन दिया है।

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में 'जंतर-मंतर वापस लाओ' अभियान के तहत मार्च पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर-मंतर की ओर निकाला गया। संगठन ने आरोप लगाया कि हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अन्य नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग किया। उसने इन घटनाओं की निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराने तथा जिम्मेदार पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उदय भानु चिब ने कहा कि जंतर-मंतर लोकतांत्रिक विरोध का प्रतीक है और इसे जनता से दूर नहीं किया जाना चाहिए।

वहीं, एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पुलिस की कथित मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने का मौखिक आश्वासन दिया।

जाखड़ ने कहा कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट गंभीर मामला है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यदि तय समय में प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, तो वे प्रतिनिधिमंडल के साथ दोबारा थाने पहुंचेंगे। एनएसयूआई ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

'ब्रिक्स समिट से दूर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हाथ से निकल गया। हसीना ने तर्क दिया कि एक जिम्मेदार सरकार को "देश के लिए दरवाजे खोलने चाहिए, बंद नहीं करने चाहिए।" उन्होंने चेतावनी दी कि व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं या अल्पकालिक राजनीतिक गणनाओं से प्रेरित विदेश नीति का परिणाम स्वाभाविक रूप से नुकसानदेह होता है।

निर्वासन में भारत में रह रहीं हसीना ने संकेत दिया कि भारत में उनकी मौजूदगी ने शायद रहमान के फैसले को प्रभावित किया हो। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है, तो यह "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" है। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और तारिक रहमान के पिता, पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान, 1979 में नई दिल्ली आए थे। उस समय हसीना 1975 में अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या के बाद भारत में रह रही थीं। जियाउर रहमान 1980 में लंदन भी गए थे, जब हसीना वहां थीं। हसीना ने कहा, "किसी भी शहर में मेरी मौजूदगी ने उन्हें वहां आने से नहीं रोका था। तो फिर आज दिल्ली में मेरी मौजूदगी जियाउर रहमान के बेटे तारिक रहमान को भारत आने से क्यों रोके?" विश्लेषकों का कहना है कि सम्मेलन से दूर रहकर रहमान ने तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक संभावित असहज बहुपक्षीय स्थिति से बचने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं से सीधे बातचीत करने और भारत के प्रति खुलेपन का संकेत देने का अवसर गंवा दिया। नवंबर में संभावित द्विपक्षीय यात्रा को लेकर चर्चा जारी है, हालांकि ढाका का कहना है कि यात्रा का समय "अनुकूल" होना चाहिए।

इस बीच, बांग्लादेश हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर जोर दे रहा है। वर्ष 2024 में हुई कार्रवाई से जुड़े आरोपों में नवंबर 2025 में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मृत्युदंड सुनाया था। भारत ने कहा है कि किसी भी प्रत्यर्पण के लिए एक सुव्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अभी तक कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की गई है और अनुरोध की जांच जारी है। हसीना ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है और दिसंबर तक लौटने का संकल्प जताया है।

'तिरंगे के साथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गिरफ्तार किया गया है। हम सबको तिरंगा लेकर वहां पहुंचना चाहिए और सरकार को यह दिखाना चाहिए की तिरंगा लहराना कोई जुर्म नहीं है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

तारानगर में सरपंच बनने की सनक में इकलौते बेटे और बहू की हत्या

विवाद व समझाइश के बाद घर जा रहे पुत्र-पुत्रवधु को रामचन्द्र ने बोलेरो गाड़ी से कुचल कर मार दिया

तारानगर, 14 अक्टूबर। तहसील क्षेत्र में पहली बार ग्राम पंचायत बने चंगोई गांव में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां गत रात्रि को सरपंच बनने की सनक में एक पिता ने विवाद के बाद अपने इकलौते बेटे व बहू को गाड़ी से कुचलकर मार डाला। गांव में हुए इस दोहरे हत्याकांड की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया।

हत्याकांड के आरोपी पिता को गांव से हिरासत में लेकर घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया गया। वारदात की सूचना पर राजगढ़ एएसपी रिछपाल चारण, डीएसपी रोहित सांखला, एसएचओ पुष्पेन्द्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया। साथ ही चूरू से एफएसएल टीम भी पहुंची।

- **प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामचन्द्र सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता था। उसका पुत्र उन्हें मना कर रहा था। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने लड़ाई-झगड़ा शुरु किया। समझा बुझाकर पुत्र व पुत्रवधु देर रात घर पैदल वापस जा रहे थे, जब आरोपी ने पीछे से गाड़ी से उन्हें कुचल दिया।**

डीएसपी रोहित सांखला ने बताया कि रात को गांव में किसी वाहन की टक्कर से दो जनों की मौत की सूचना मिली। वे मय जाब्ते के घटना स्थल पर पहुंचे, तो दो जनों के शव पड़े थे। गहनता से जांच करने व सीसीटीवी देखने पर पता चला कि घटना को अंजाम देने वाला मृतक युवक रवीन्द्र का पिता रामचन्द्र था। घटना से थोड़ी देर पहले गांव में स्थित खुद के धर्मकांटे पर पिता-पुत्र में चुनाव लड़ने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें आरोपी सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता था और पुत्र उसे मना कर रहा था। विवाद बढ़ने पर मृतक रवीन्द्र की पत्नी महेन्द्रा भी मौके पर पहुंची और आरोपी को समझा बुझाकर बेटे-बहू वापिस घर जा रहे थे। उसी दौरान रात्रि 12:45 बजे आरोपी रामचंद्र पीछे से बोलेरो गाड़ी लेकर आया और दोनों को कुचल दिया, जिससे बेटे व बहू की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर आगे की करवाई शुरू कर दी है। मृतक रवीन्द्र के ससुर ने मामला दर्ज कराया है। एसएचओ पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि शिशराम पुत्र दुलाराम जाट निवासी मैलूसर पीएस भालेरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री महन्द्रा का विवाह करीब 15 वर्ष पूर्व रवाद्र पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी चंगोई के साथ हुआ था, जिनके एक पुत्री मितारिका (11) है। मृतक रवीन्द्र के ससुर ने बताया कि 13 व14 अक्टूबर की रात्रि एक बजे के लगभग दोनों बाप-बेटे अपने धर्मकांटे पर बैठे थे और चुनाव लड़ने की बात को लेकर आपस में विवाद हो गया। उनकी बेटी महेन्द्रा अपने पति रवीन्द्र को समझा बुझाकर घर ला रही थी, उसी दौरान आरोपी पीछे से गाड़ी लेकर आए और दोनों को गाड़ी से कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस दौरान मृतक दंपति की 11 वर्षीय बेटी मितारिका भी मौके पर मौजूद थी। मीतारिका अपनी माँ के पीछे-पीछे जा रही थी, जब वह यादव धर्मकांटे के पास पहुंची तो उसने उक्त सारी घटना अपनी आँखो से देखी।

'अमेरिका में मोदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि एक अमेरिकी सार्वजनिक हस्ती का भारत के विरोध प्रदर्शन से जुड़े आंदोलन पर टिप्पणी करना राजनीतिक रूप से क्या मायने रखता है। हालांकि, इससे फंडिंग को लेकर उठे सवाल का अपने आप समाधान नहीं हुआ।

अब यह विवाद एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दावों के बजाय, सबूतों पर टिका है। दानदाताओं की पहचान, बैंक रिकॉर्ड, दान की रसीदें, ऑडिट किए गए खाते या भरोसेमंद जांच के नतीजे यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि पैसा विदेश से आया था या नहीं और क्या वह संगठन तक पहुंचा था। नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका फैसला दान की प्रकृति, संगठन के कानूनी स्टेटस और उस पर लागू होने वाले नियमों पर निर्भर करेगा।

सीजेपी से आगे भी इस मुद्दे के व्यापक मायने हैं। विदेशी फंडिंग के आरोप राजनीतिक विरोध के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। जबकि, बिना पुष्टि किए गए आरोप घरेलू विरोध को बाहरी दखलंदाजी से जोड़कर उनकी निष्पक्ष जांच को कमजोर कर सकते हैं। दूसरी ओर, बिना बताई गई फंडिंग के पक्के सबूत मिलने पर पारदर्शी जांच होनी चाहिए, चाहे इसमें शामिल लोगों की राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो।

फिलहाल, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सबूतों की समीक्षा के आधार पर यह दावा साबित नहीं हुआ है कि अमेरिकी दानदाता दीपके की सीजेपी को पैसा दे रहे हैं। इस आरोप ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता आखिरकार इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या पैसों के लेन-देन से जुड़े ठोस और जांचे जा सकने वाले सबूत सामने आते हैं।

नीला ड्रम हत्याकांड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहले उनकी दिनचर्या और अपने पक्ष में कुछ कहने की इजाजत दी, लेकिन दोनों ने कहा कि वे कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं।

हालांकि मुस्कान ने अपनी बेटी से मिलने की गुजारिश न्यायालय से की। बचाव पक्ष की अधिवक्ता रेखा जैन ने बच्चियों के भविष्य और पालन-पोषण का हवाला देते हुए अदालत से कम सजा देने की अपील की। लंच के बाद कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और दलीलों और बयान के आधार पर दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424, हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908